

सरकारी वित्त 2025-26: एक अर्ध-वार्षिक समीक्षा

बाई अमृता बसु, आकाश राज, हर्षित यादव,
देबप्रिया साहा, आयुषी खंडेलवाल, अनूप के
सुरेश, श्रोमोना गांगुली और अत्रि मुखर्जी[^]

पहली छमाही: 2025-26 के दौरान केंद्र और राज्यों की राजकोषीय स्थिति लचीली रही। उनकी प्राप्ति मोटे तौर पर पहली छमाही: 2024-25 के दौरान देखे गए रुझानों के अनुरूप थीं। केंद्र और राज्यों दोनों ने पूंजीगत व्यय को बनाए रखते हुए राजस्व व्यय को नियंत्रित करने के माध्यम से विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। इसके परिणामस्वरूप केंद्र के साथ-साथ राज्यों के लिए व्यय की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जो मध्यम अवधि के विकास की संभावनाओं और राजकोषीय समेकन के लिए अच्छा संकेत है।

परिचय

केंद्रीय बजट 2025-26 ने विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप समावेशी, दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए राजकोषीय अनुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। विकास के चार इंजनों - कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात के तहत, बजट में अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक संरचनात्मक परिवर्तन के साथ सामाजिक-आर्थिक जरूरतों को संतुलित करने के लिए कई उपाय शामिल थे। बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर जारी रखते हुए, बजट 2025-26 में पूंजीगत व्यय के लिए ₹11.2 लाख करोड़ (सकल घरेलू उत्पाद का 3.1 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया। इसी तरह, प्रभावी पूंजीगत व्यय¹ को 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 4.3 प्रतिशत पर रखा गया था, जो 2024-25 के संशोधित अनुमानों

[^] यह लेख श्रीमती संगीता दास के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। लेखक भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग में काम कर रहे हैं। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

¹ प्रभावी पूंजीगत व्यय पूंजीगत व्यय और पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान सहायता का योग है। 2024-25 के लिए, प्रभावी पूंजीगत व्यय पर उपलब्ध नवीनतम डेटा संशोधित अनुमान है।

(आरई) के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के 4.0 प्रतिशत से अधिक है।

इसके अलावा, राज्यों के पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने की दिशा में, पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत आवंटन को पिछले वर्ष से बढ़ाया गया था। केंद्र का राजस्व व्यय 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के 10.9 प्रतिशत (अंतिम खाते, पीए) से मामूली रूप से बढ़कर 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद का 11.0 प्रतिशत (बजट अनुमान, बीई) होने का अनुमान लगाया गया था। कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट का उद्देश्य 2025-26 तक सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से नीचे लाने के मध्यम अवधि के लक्ष्य के अनुरूप राजकोषीय सुदृढ़ीकरण करना है।

कुशल राजकोषीय और वृहद-आर्थिक परिणामों के लिए उप-वार्षिक सार्वजनिक वित्त का विश्लेषण करने के महत्व को स्वीकार करते हुए, यह लेख केंद्र के साथ-साथ राज्यों के लिए छमाही राजकोषीय स्थिति का एक संक्षिप्त दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। पहली छमाही: 2025-26 के दौरान, केंद्र का जीएफडी 2024-25 की पहली छमाही में बजट अनुमान के 29.4 प्रतिशत की तुलना में बजट अनुमान का 36.5 प्रतिशत रहा, जो मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय में मजबूत वृद्धि के कारण है। प्राप्ति के पक्ष में, गैर-कर स्रोतों और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति के माध्यम से उच्च संग्रह ने केंद्र के लिए कर राजस्व की कमी को दूर करने में मदद की। राज्यों के मामले में, जीएफडी पहली छमाही: 2025-26 में उनके बजट अनुमान का 37.6 प्रतिशत रहा, जो पहली छमाही: 2024-25 के दौरान दर्ज किए गए अपने स्तर से मामूली अधिक है, जो मुख्य रूप से उनकी राजस्व प्राप्ति में सुस्त वृद्धि के कारण है। व्यय के मोर्चे पर, राज्यों ने अपने राजस्व व्यय की गति को बनाए रखा, जबकि पूंजीगत व्यय में मामूली वृद्धि^{4,5} दर्ज की गई।

² 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता' योजना के लिए आवंटन 2024-25 (आरई) में ₹1.25 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2025-26 (बजट अनुमान) में ₹1.5 लाख करोड़ कर दिया गया था।

³ जैसा कि केंद्रीय बजट, 2021-22 में घोषित किया गया है।

⁴ डेटा 23 राज्यों से संबंधित है जिनके लिए अप्रैल-सितंबर 2025 के आंकड़े उपलब्ध हैं। जीएफडी-जीडीपी अनुपात का अनुमान उन्हीं 23 राज्यों के जीएसडीपी आंकड़ों का उपयोग करके लगाया जाता है।

⁵ केंद्र के साथ-साथ राज्यों की छमाही और त्रैमासिक वित्तीय स्थिति के संबंध में विस्तृत विवरण परिशिष्ट सारणी (I से IV) में दिए गए हैं।

शेष लेख इस प्रकार संरचित है: खंड II पहली छमाही: 2025-26 के दौरान केंद्र और राज्यों की प्राप्ति और व्यय (त्रैमासिक आवृत्ति पर) का विश्लेषण करता है। खंड III केंद्र के साथ-साथ राज्यों के लिए घाटे के संकेतकों और उनके वित्तपोषण के संदर्भ में परिणामों से संबंधित है। खंड IV पहली छमाही: 2025-26 के लिए सामान्य सरकार (केंद्र और राज्यों) के वित्त पर अनुमान प्रस्तुत करता है। खंड V समापन टिप्पणियों को निर्धारित करता है।

II. ति.1 और ति.2 में राजकोषीय परिणाम

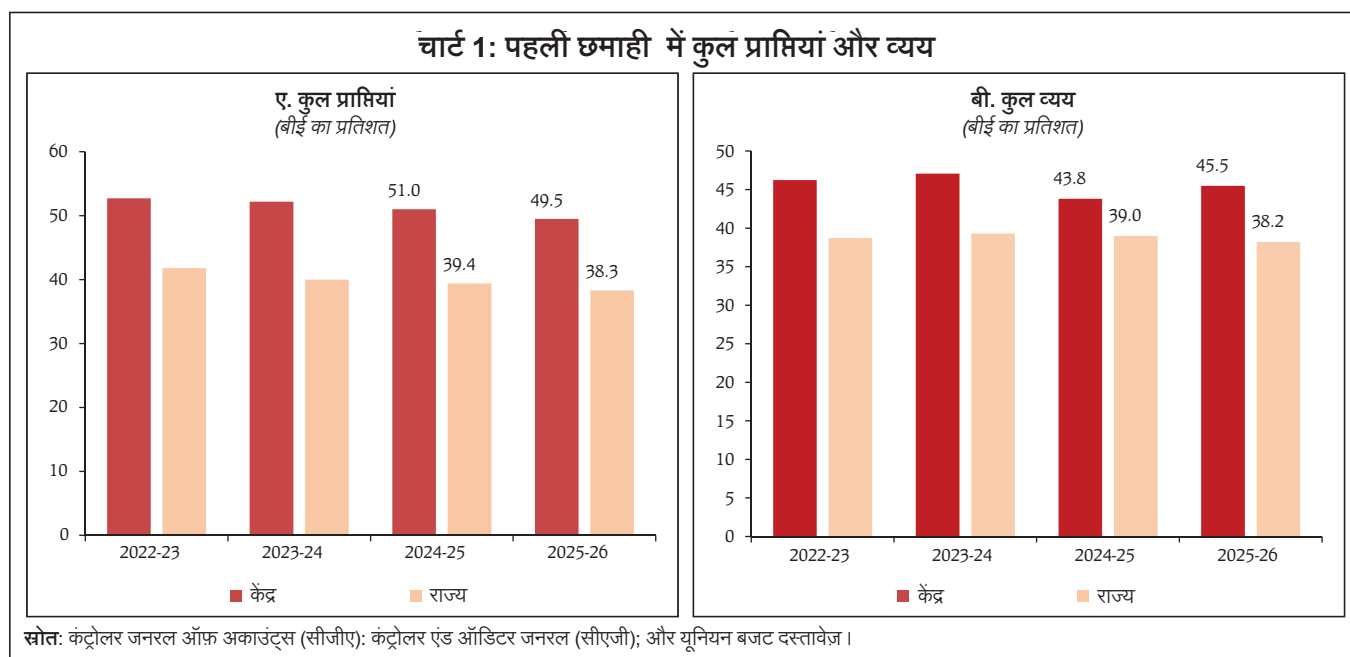
पहली छमाही: 2025-26 के दौरान, केंद्र सरकार ने अपनी कुल बजटीय प्राप्तियों का लगभग 50 प्रतिशत एकत्र किया, जो पिछले वर्ष के संग्रह से थोड़ा कम है। साल-दर-साल (वर्ष-दर-वर्ष) आधार पर, पहली छमाही: 2025-26 के दौरान कुल प्राप्तियों में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। केंद्र का कुल व्यय पहली छमाही: 2025-26 में बजट अनुमान के 50 प्रतिशत से कम था, जो पिछले तीन वर्षों के दौरान देखे गए पैटर्न के अनुरूप था (चार्ट 1a और b)। बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में राज्यों की कुल प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में कमी देखी गई (चार्ट 1 ए)। यह केंद्र⁶ से अनुदान में संकुचन और राज्यों के माल और सेवा कर

(एसजीएसटी) में धीमी वृद्धि के कारण था। व्यय पक्ष पर, राज्यों ने पहली छमाही: 2025-26 के दौरान अपने बजटीय परिव्यय का 38.2 प्रतिशत खर्च किया है, जो उनके पिछले खर्च पैटर्न (चार्ट 1b) के अनुरूप है।

ए . प्राप्तियाँ

केंद्र की कुल प्राप्तियों (यानी, 'कुल गैर-ऋण प्राप्तियाँ') में राजस्व प्राप्तियाँ और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ शामिल हैं। पहली छमाही: 2025-26 के दौरान, केंद्र सरकार की कुल गैर-ऋण प्राप्तियाँ बजट अनुमान का 49.5 प्रतिशत रहीं, जिसमें राजस्व प्राप्तियाँ और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ उनके बजटीय लक्ष्य का क्रमशः 49.6 प्रतिशत और 45.8 प्रतिशत प्राप्त हुईं। मुख्य रूप से कर प्राप्तियों में कम वृद्धि के कारण, पहली छमाही: 2025-26 के दौरान केंद्र की प्राप्तियाँ (बजट अनुमान के प्रतिशत के अनुसार) पहली छमाही: 2024-25 के दौरान प्राप्त इसी आंकड़े से मामूली कम रही। ति. 1:2025-26 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि ति. 1:2024-25 की तुलना में धीमी थी, जिसकी आंशिक रूप से गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की मजबूत वृद्धि से भरपाई की गई थी⁷। हालांकि, ति. 2:2025-26 में, राजस्व

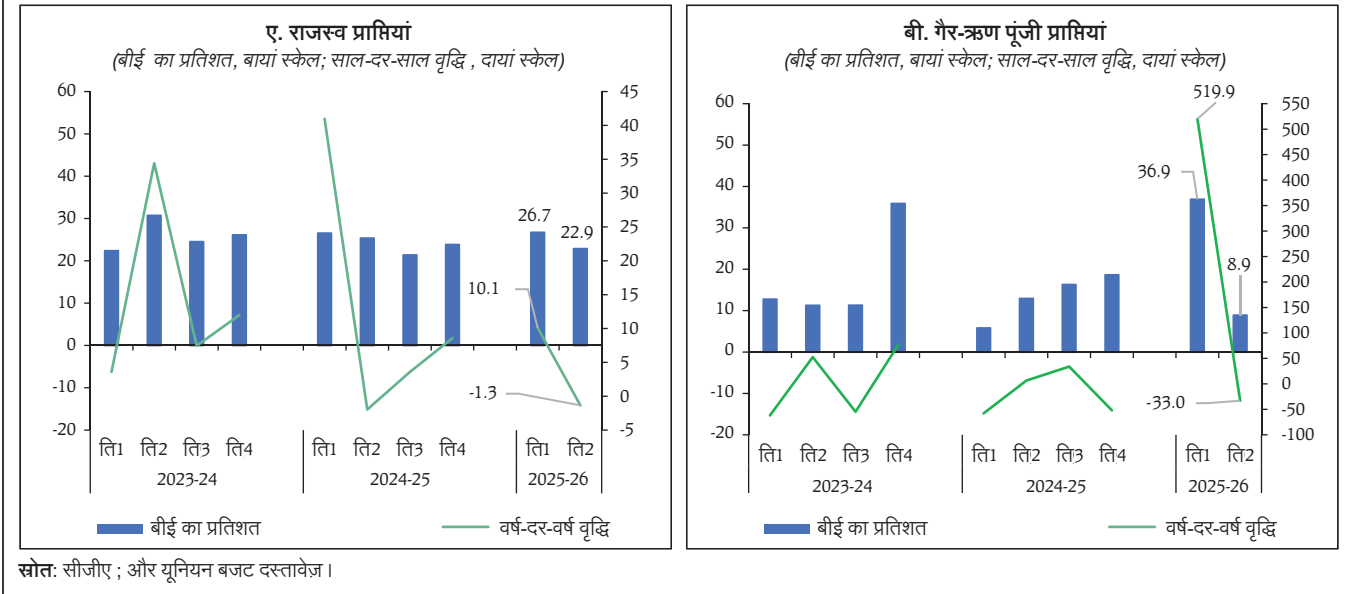
चार्ट 1: पहली छमाही में कुल प्राप्तियाँ और व्यय



⁶ वित्त आयोग के अनुदानों में आंशिक रूप से कटौती के कारण केंद्र से अनुदान में गिरावट जारी रही।

⁷ गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों और अग्रिमों की वसूली और विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ (जैसे, विनिवेश और अन्य प्राप्तियाँ) शामिल हैं।

चार्ट 2: केंद्र की गैर-ऋण प्राप्ति का तिमाही ब्योरा

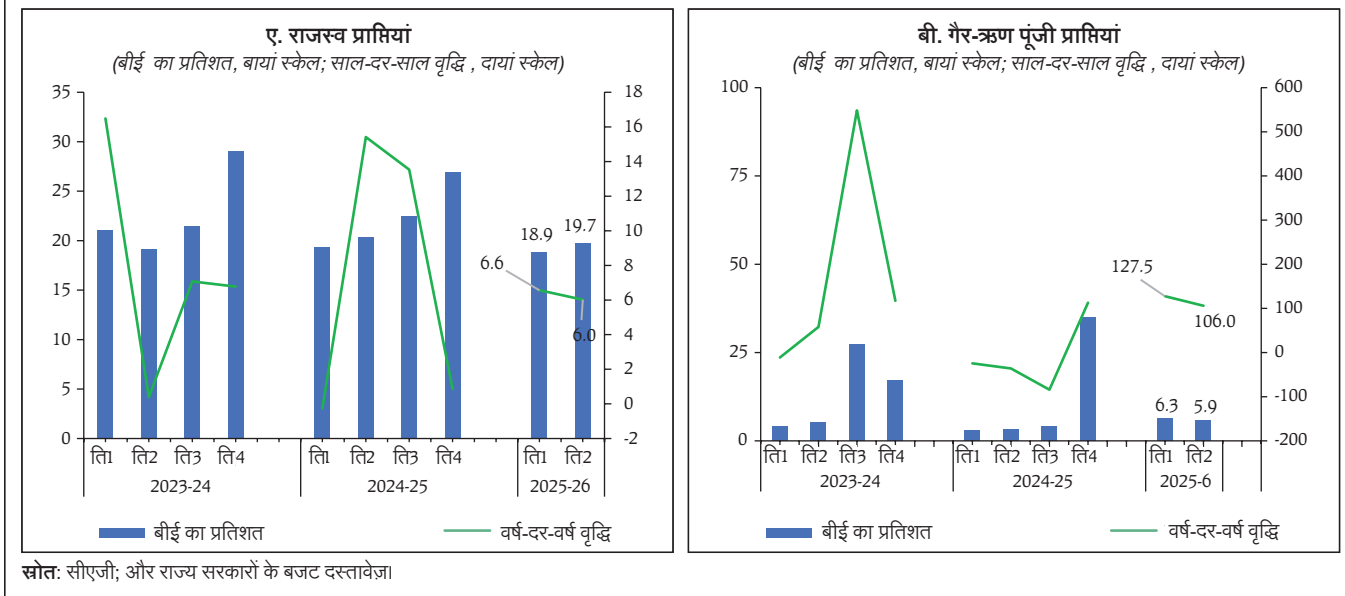


प्राप्तियों और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों दोनों ने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर संकुचन दर्ज किया (चार्ट 2a और b)।

राज्यों की राजस्व प्राप्तियों ने पहली छमाही: 2025-26 में 6.3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की, आंशिक रूप से एसजीएसटी संग्रह में कमजोर गति के कारण (चार्ट 3a)। कर राजस्व, जो दो-तिहाई से अधिक है (चार्ट 2 ए और बी)। राज्यों की राजस्व प्राप्तियों ने पहली छमाही: 2025-26 में 6.3 प्रतिशत

की मामूली वृद्धि दर्ज की, आंशिक रूप से एसजीएसटी संग्रह में कमजोर गति के कारण (चार्ट 3a)। कर राजस्व, जो राजस्व प्राप्तियों का दो-तिहाई से अधिक है, ने 2025-26 की पहली तिमाही और 2025-26 की दूसरी तिमाही में क्रमशः 7.3 प्रतिशत और 11.1 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित की। साथ ही, राज्यों की गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों⁸ ने दोनों तिमाहियों में मजबूत वृद्धि दर्ज की (चार्ट 3 बी)।

चार्ट 3: राज्यों की प्राप्तियों का तिमाही ब्योरा



8 राज्यों की गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में उनके द्वारा अधीनस्थ/पैरास्टेटल संस्थाओं को संवितरित ऋणों और अग्रियों की वसूली और अन्य विविध पूंजीगत प्राप्ति शामिल हैं।

केंद्र का प्रत्यक्ष कर संग्रह 2025-26 की पहली छमाही में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 3.0 प्रतिशत बढ़ा, जिसका मुख्य कारण आयकर संग्रह में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि कॉर्पोरेट कर संग्रह में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पहली छमाही: 2024-25 में देखे गए पैटर्न के समान, आयकर संग्रह पहली छमाही: 2025-26 में कॉर्पोरेट कर संग्रह से अधिक हो गया, जो अन्य बातों के साथ-साथ, करदाताओं के अनुपालन में सुधार और कर आधार को व्यापक बनाने की दिशा में उपायों को दर्शाता है⁹ (चार्ट 4 ए)। राज्यों के अपने प्रत्यक्ष कर संग्रह (जिसमें भूमि राजस्व और स्टॉप शुल्क और पंजीकरण शुल्क से प्राप्तियां शामिल हैं) ने स्टॉप शुल्क (चार्ट 4 बी) से मजबूत संग्रह द्वारा बड़े पैमाने पर संचालित एक स्थिर वृद्धि दर्ज की।

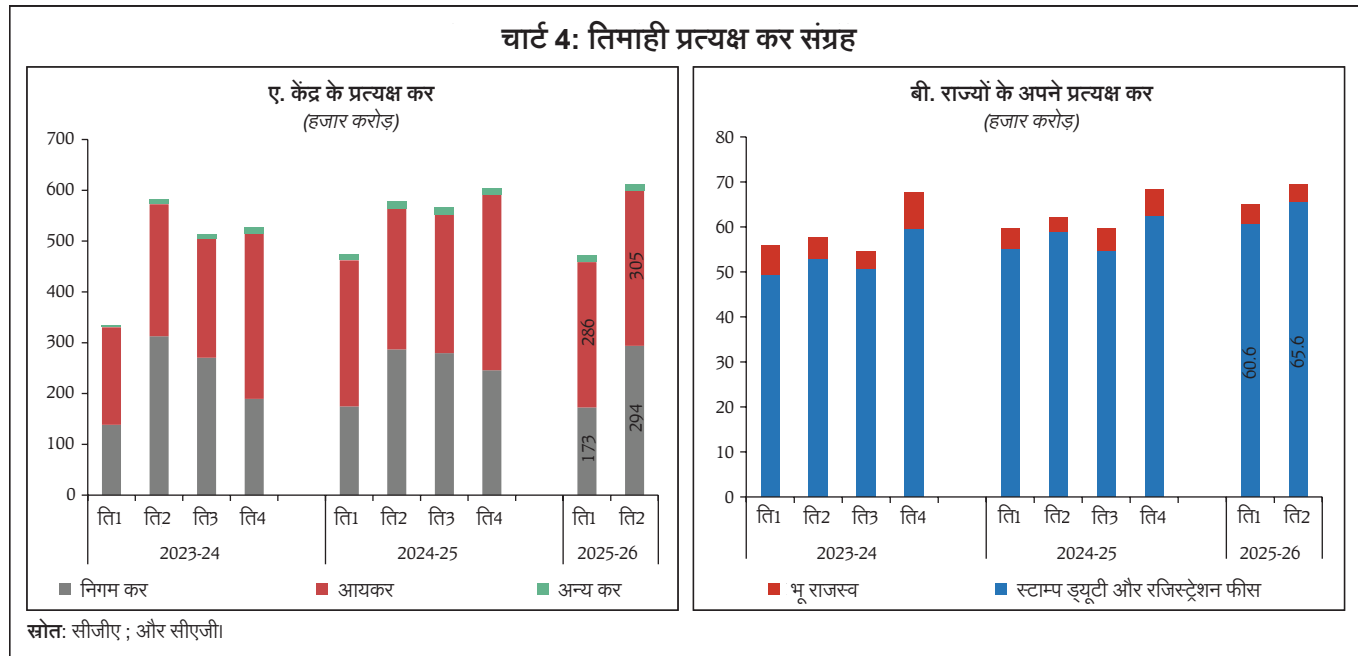
केंद्र का अप्रत्यक्ष कर संग्रह पहली छमाही: 2025-26¹⁰ में 2.6 प्रतिशत (वर्ष -दर-वर्ष) बढ़ गया। इसका मुख्य कारण जीएसटी और उत्पाद शुल्क में वृद्धि को दिया गया, जबकि सीमा शुल्क से राजस्व में गिरावट आई। विशेष रूप से, मजबूत जीएसटी संग्रह (16.1 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि) ने ति. 1:2025-26 में कुल अप्रत्यक्ष करों में 11.3 प्रतिशत की दोहरे अंकों की वृद्धि में

योगदान दिया। हालांकि, 2025-26 की दूसरी तिमाही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क को छोड़कर, सभी अप्रत्यक्ष कर श्रेणियों में राजस्व संग्रह वर्ष-दर-वर्ष आधार पर संकुचित हुआ। कुल मिलाकर, पहली छमाही: 2025-26 में, केंद्र अपने बजटीय अप्रत्यक्ष करों का 44.6 प्रतिशत एकत्र कर सका, जबकि पहली छमाही: 2024-25 के दौरान यह 46.6 प्रतिशत था।

पहली छमाही: 2025-26 में सकल GST संग्रह (केंद्र और राज्य) ₹ 11.9 लाख करोड़ था, जिसमें 9.8 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई (पहली छमाही: 2024-25 में 9.5 प्रतिशत की वृद्धि) दर्ज की गई, जिसमें ति. 1:2025-26 और ति. 2:2025-26 में क्रमशः ₹2.1 लाख करोड़ और ₹1.9 लाख करोड़ का औसत मासिक संग्रह (चार्ट 5) दर्ज किया गया। जीएसटी राजस्व को डिजिटल एकीकरण में सुधारों, अनुपालन प्रक्रियाओं को आसान बनाने और 2017 में इसकी स्थापना के बाद से किए गए दर युक्तिकरण उपायों से समर्थन प्राप्त करना जारी है (बॉक्स ए)।

राज्यों के मामले में, कर राजस्व की वृद्धि में कमी मुख्य रूप से राज्यों के जीएसटी (एसजीएसटी) (चार्ट 6ए)¹¹ के संग्रह पर अप्रैल 2025 में एसजीएसटी के एकमुश्त नकारात्मक निपटान

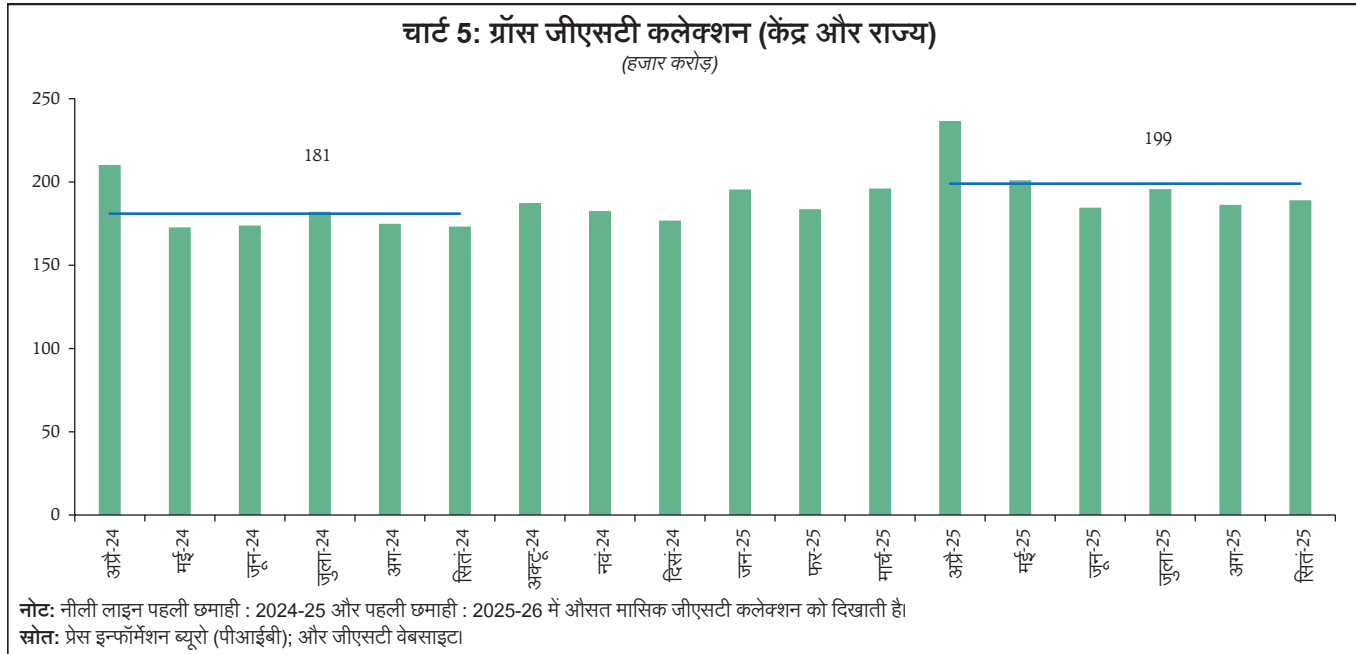
चार्ट 4: तिमाही प्रत्यक्ष कर संग्रह



⁹ <https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?id=154926&NotelD=154926&ModuleId=3>

¹⁰ पहली छमाही :2024-25 के दौरान केंद्र का अप्रत्यक्ष कर संग्रह 2023-24 की पहली छमाही की तुलना में 8.4 प्रतिशत बढ़ा।

¹¹ राज्यों का जीएसटी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के जीएसटी राजस्व और आईजीएसटी में उनकी हिस्सेदारी का योग है। अप्रैल 2025 के दौरान, पुरानी आईजीएसटी कमी को पूरा करने के लिए 23,000 करोड़ रुपये का निपटान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों के लिए जीएसटी राजस्व में गिरावट आई।



बॉक्स ए : भारत में जीएसटी सुधारों के आठ साल का पता लगाने का काम

1 जुलाई, 2017 को पूरे भारत में लागू किए गए माल और सेवा कर (जीएसटी) ने केंद्रीय मूल्य वर्धित कर, केंद्रीय बिक्री कर, राज्य बिक्री कर और चुंगी जैसे कई करों को बदल दिया था। अपनी शुरुआत के आठ साल बाद, जीएसटी ने खुद को सरल और अधिक पारदर्शी ढांचे के रूप में मजबूती से स्थापित किया है, हाल के साक्ष्य इसके प्रगतिशील वितरण प्रभाव का संकेत देते हैं (मुखर्जी, 2025)। राजस्व संग्रह में लगातार वृद्धि और 1.5 करोड़ से अधिक सक्रिय करदाताओं का बढ़ता आधार इसकी सफलता का प्रमाण है। औसत मासिक जीएसटी संग्रह ने पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाया है और अप्रैल-अक्टूबर 2025 की अवधि के लिए यह 1.98 लाख करोड़ रुपये रहा, जो अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान प्राप्त 1.82 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। शुद्ध जीएसटी संग्रह (सकल जीएसटी संग्रह, कम रिफंड) काफी हद तक सकल जीएसटी संग्रह (चार्ट ए.1 और ए.2) की प्रवृत्ति के अनुरूप है।

अपनी स्थापना के बाद से, जीएसटी ढांचा एक सुव्यवस्थित और व्यापक डिजिटल बुनियादी ढांचे की स्थापना की दिशा में लगातार विकसित हो रहा है; करदाताओं के लिए अनुपालन में आसानी बढ़ाना; एक पारदर्शी और कुशल संघीय ढांचे को बढ़ाना; विभिन्न हितधारकों द्वारा सुधारों का

पालन सुनिश्चित करना और दर युक्तिकरण उपायों के माध्यम से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर 12 के मुद्दों को संबोधित करना।

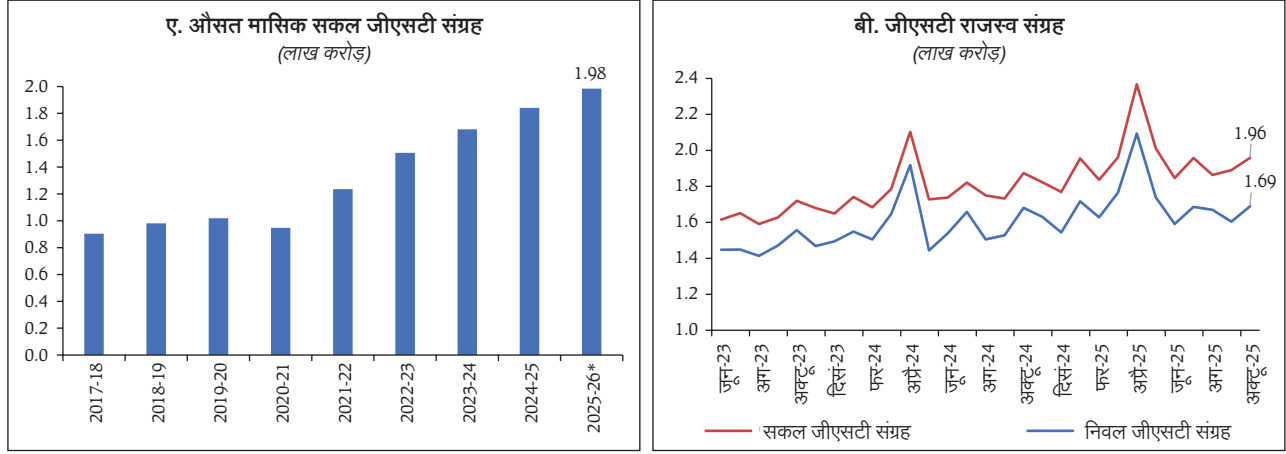
जीएसटी के तहत एकल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की शुरुआत ने अनुपालन को सुव्यवस्थित करके और कई सरकारी डेटाबेस के एकीकरण के लिए नींव बनाकर भारत के कर प्रशासन में एक प्रमुख डिजिटल परिवर्तन को चिह्नित किया [माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) की स्थापना के माध्यम से, जो भारत के अप्रत्यक्ष कर पारिस्थितिकी तंत्र की केंद्रीय डिजिटल रीढ़ है]। सामान्य पोर्टल के माध्यम से, जीएसटीएन करदाताओं के पंजीकरण, रिटर्न फाइलिंग, भुगतान और अन्य अनुपालनों का समर्थन करता है। जीएसटीएन केंद्र और राज्यों के बीच एक साझा बुनियादी ढांचा है जो कर संग्रह में पारदर्शिता में सहायता करता है, जिससे राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा मिलता है (भारत सरकार, 2019)।

2018 में शुरू की गई ई-वे बिल 13 प्रणाली ने माल की अंतर-राज्य और राज्य के भीतर सुचारु आवाजाही को सक्षम करके और चेक-पोस्ट कागजी कार्रवाई को कम करके व्यापार करने में आसानी में काफी सुधार किया। इसके बाद, सितंबर 2019 में, जीएसटी परिषद ने ई-चालान 14 की शुरुआत को मंजूरी दी, जो शुरू में 500 करोड़ रुपये और उससे (जारी)

¹² इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां आउटपुट पर कर इनपुट पर कर से कम होता है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का संचय होता है, जिसका कार्यशील पूंजी और फर्मों की तरलता पर प्रभाव पड़ सकता है। जीएसटी कानून कुछ विशिष्ट मामलों को छोड़कर, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 (3) के तहत उल्टे शुल्क संरचना के कारण संचित आईटीसी की वापसी की अनुमति देता है।

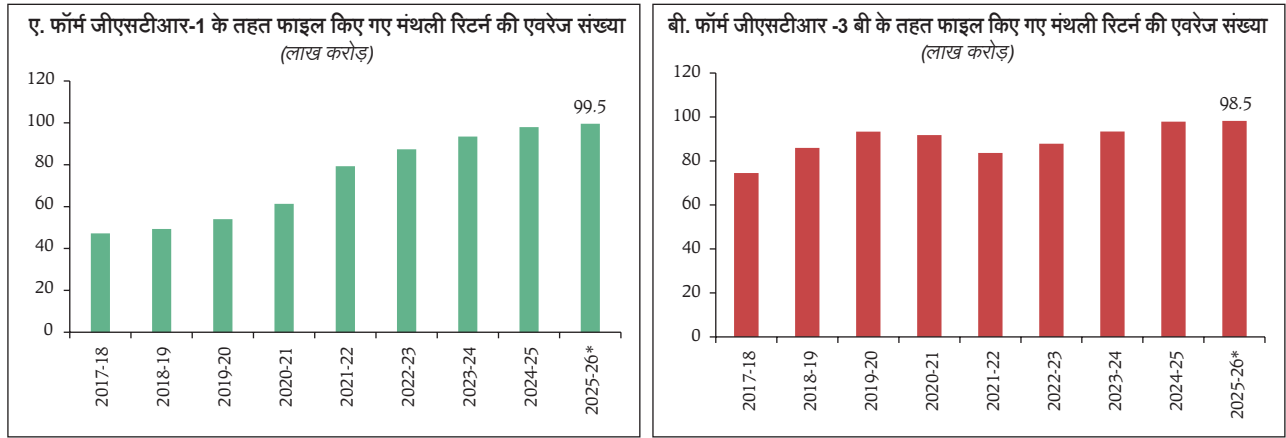
¹³ ई-वे बिल एक अनुपालन तंत्र है, जिसमें एक डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से, माल की आवाजाही का कारण बनने वाला व्यक्ति (₹50,000 से अधिक के खेप मूल्य के साथ) माल की आवाजाही शुरू होने से पहले प्रासंगिक जानकारी अपलोड करता है। ई-वे बिल में कंसाइनर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर का नाम, माल की आवाजाही का मूल बिंदु और उसका गंतव्य जैसे विवरण होते हैं।

चार्ट ए .1: जीएसटी कलेक्शन के ट्रेंड्स



*: 2025-26 के लिए, डेटा अप्रैल-अक्टूबर 2025 के समय से जुड़ा है।
नोट: नेट जीएसटी कलेक्शन का मतलब है ग्राँस जीएसटी कलेक्शन में से रीफंड घटाकर।
स्रोत: जीएसटी सांख्यिकी, भारत सरकार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश।

चार्ट ए .2 : फाइल किए गए जीएसटी रिटर्न के ट्रेंड



*:2025-26, डेटा अप्रैल-अक्टूबर 2025 के समय का है।
नोट : 1. फॉर्म जीएसटीआर -1 टैक्सपेयर्स द्वारा दिया जाने वाला एक मंथली स्टेटमेंट है, जिसमें गूड्स और सर्विसेज या दोनों की आउटवर्ड सप्लाय की डिटेल्स होती हैं।
 2. फॉर्म जीएसटीआर -3बी टैक्सपेयर्स के लिए एक आसान समरी रिटर्न है, जिससे वे किसी खास टैक्स पीरियड के लिए अपनी समरी जीएसटी लायबिलिटीज बता सकते हैं और इन लायबिलिटीज को चुका सकते हैं।
स्रोत: जीएसटी सांख्यिकी, भारत सरकार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश।

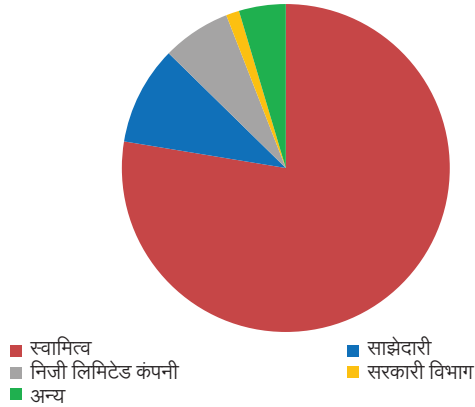
अधिक के वार्षिक कुल कारोबार वाले व्यवसायों के लिए लागू होता है। तब से सीमा को घटाकर ₹5 करोड़ कर दिया गया है, जिससे सिस्टम अधिक व्यापक हो गया है। ई-चालान की शुरुआत ने अनुपालन को स्वचालित और सरल बना दिया है क्योंकि पंजीकृत चालान से डेटा अब फॉर्म जीएसटीआर-3बी जैसे जीएसटी रिटर्न में ऑटो-पॉप्युलेट हो गया है। इसके अलावा, सिस्टम को ई-वे बिल पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जो ई-वे बिलों को तेजी से और अधिक सटीक बनाने में सक्षम बनाता है।

इनके अलावा, सिस्टम में सुधार के भीतर, जीएसटीएन निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अन्य सरकारी प्लेटफार्मों से भी जुड़ता है। उदाहरण के लिए, भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आईसीईगेट) और जीएसटी सिस्टम आयात पर इनपुट टैक्स क्रेडिट और निर्यात पर रिफंड जैसी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक डेटा का आदान-प्रदान करते हैं। इसी तरह, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए उद्यम पंजीकरण 15 पोर्टल पैना/जीएसटी से जुड़े डेटाबेस पर आधारित है, जिससे उद्यमों के (जारी)

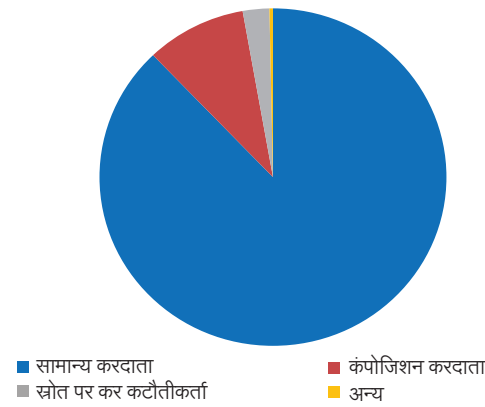
¹⁴ ई-चालान में सरकार द्वारा अधिसूचित पोर्टल पर निर्दिष्ट जीएसटी दस्तावेजों के विवरण की रिपोर्ट करना और एक संदर्भ संख्या प्राप्त करना शामिल है।
¹⁵ उद्यम पंजीकरण एमएसएमई के लिए एक वैकल्पिक पंजीकरण तंत्र है। यह एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं जैसे क्रेडिट गारंटी योजना, सार्वजनिक खरीद नीति, और सरकारी निविदाओं में अतिरिक्त बटव और विलंबित भुगतान के खिलाफ सुरक्षा, और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का लाभ उठाने में एमएसएमई का समर्थन करता है [भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का पंजीकरण, 2020-22, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार]।

चार्ट ए.3: प्रकार-वार जीएसटी पंजीकरण

ए. मार्च 2025 के आखिर तक जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाता



बी. अक्टूबर 2025 के आखिर तक सक्रिय करदाता



नोट: 1. चार्ट 3ए में अन्य में सीमित देयता भागीदारी, सोसायटी/क्लब/ट्रस्ट/एओपी, स्थानीय प्राधिकरण, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी और हिंदू अविभाजित परिवार शामिल हैं।
2. चार्ट 3बी में दूसरे टैक्सपेयर्स में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, कैजुअल टैक्सपेयर्स, टैक्स कलेक्टर एट सोर्स और नॉन-रेसिडेंट टैक्सपेयर्स शामिल हैं।
स्रोत: जीएसटी सांख्यिकी, भारत सरकार, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश।

लिए सरकारी योजनाओं तक पहुंचना आसान हो जाता है। इन डिजिटल लिंकेज ने डेटा गैप को कम किया है, कर और व्यापार प्रणालियों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित किया है और पारदर्शिता को मजबूत किया है।

जीएसटी 16 के तहत 1.5 करोड़ पंजीकृत करदाताओं में से 77.6 प्रतिशत स्वामित्व हैं, जो कर आधार में छोटे व्यवसायों की प्रबलता को दर्शाते हैं और सरलीकृत अनुपालन तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं (चार्ट ए.3ए)। छोटे करदाताओं के लिए अनुपालन में आसानी जीएसटी ढांचे के माध्यम से किया गया एक महत्वपूर्ण सुधार है, जो अर्थव्यवस्था के करदाता-अनुकूल औपचारिकता का मार्ग प्रशस्त करता है। जीएसटी कंपोजिशन योजना को छोटे करदाताओं पर अनुपालन बोझ को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जिससे उन्हें व्यक्तिगत लेनदेन के बजाय वार्षिक कारोबार के आधार पर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अनुमति मिल सके। अक्टूबर 2025 के अंत तक जीएसटी के तहत कुल पंजीकृत करदाताओं में ये कंपोजिशन करदाता लगभग 9.3 प्रतिशत हैं (चार्ट ए.3बी)। कुल कंपोजिशन करदाताओं में से लगभग 6.2 प्रतिशत विशेष श्रेणी के राज्यों से थे। विशेष श्रेणी के राज्यों को छोड़कर, कुल करदाताओं के प्रतिशत के रूप में कंपोजिशन करदाताओं

की संख्या आंध्र प्रदेश (19.9 प्रतिशत) में सबसे अधिक थी, इसके बाद छत्तीसगढ़ (15.8 प्रतिशत), बिहार और उत्तर प्रदेश (प्रत्येक मामले में 15.5 प्रतिशत) का स्थान था। क्रॉस-कंट्री अनुभव से पता चलता है कि सरलीकृत कर व्यवस्थाएं, जब सावधानी से डिजाइन की जाती हैं, तो संभावित रूप से छोटे उद्यमों के लिए अनुपालन लागत को कम कर सकती हैं (एंगेल्सचॉक और लोप्रिक, 2015)।

पिछले आठ वर्षों में, जीएसटी परिषद द्वारा दरों की आवधिक समीक्षा के माध्यम से कर प्रणाली को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं ताकि इन्वर्टेड ड्यूटी संरचना जैसे मुद्दों को हल किया जा सके और विभिन्न हितधारकों द्वारा उचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक की सिफारिशों के बाद सितंबर 2025 में घोषित सुधार थे, जिसने चार-स्लैब दर संरचना²⁰ से सरलीकृत दो-स्लैब जीएसटी फ्रेमवर्क²¹ में बदलाव को चिह्नित किया। सुधारों का उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए लागत कम करना, व्यापारियों के लिए अनुपालन को आसान बनाना और भारतीय व्यवसायों के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है। आगे बढ़ते हुए, जीएसटी दरों के परिणामस्वरूप युक्तिकरण से मांग को प्रोत्साहित करने और आर्थिक गतिविधियों को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

(जारी)

¹⁶ 31 मार्च, 2025 तक।

¹⁷ योजना वैकल्पिक है। यह अनिवार्य रूप से छोटे करदाताओं के लिए टर्नओवर कर व्यवस्था प्रदान करता है, जिसमें कर के त्रैमासिक भुगतान के साथ-साथ वार्षिक आधार पर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा होती है। इस योजना के तहत, एक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति, जिसका कुल वार्षिक कारोबार पिछले वित्तीय वर्ष में माल के मामले में 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं हुआ है (उत्तराखंड और 7 पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 75 लाख रुपये) इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं। सेवा प्रदाताओं के लिए, पिछले वित्त वर्ष में टर्नओवर की सीमा ₹50 लाख थी।

¹⁸ जैसा कि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 22 में परिभाषित किया गया है।

¹⁹ अनुपालन में सुधार के लिए हाल के उपायों में वस्तु एवं सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना, 2023 और 2024 में केंद्र और राज्य कर अधिकारियों द्वारा फर्जी पंजीकरण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान और बाहरी आपूर्ति के साथ देयता का सटीक मिलान सुनिश्चित करने के लिए ऑटो-पॉपुलेटेड, गैर-संपादन योग्य फॉर्म-3बी की शुरुआत शामिल है।

²⁰ मोटे तौर पर चार स्लैब शामिल हैं, अर्थात् 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत।

²¹ मोटे तौर पर दो स्लैब, अर्थात् 5 और 18 प्रतिशत, के साथ-साथ कुछ पाप और विलासिता की वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर शामिल है।

संक्षेप में, भारत का जीएसटी ढांचा एक गतिशील और अनुकूली प्रणाली के रूप में विकसित हुआ है, जो अपने प्रमुख हितधारकों, जैसे केंद्र, राज्यों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करता है। केंद्र और राज्यों के बीच राजकोषीय सहयोग की भावना को संरक्षित करते हुए संरचना को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ उत्तरोत्तर संरेखित करते हुए, सरलीकरण, पारदर्शिता और दक्षता पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सुधार यात्रा जारी है।

संदर्भ

Government of India (2019). The GST Saga: A Story of Extraordinary National Ambition. Ministry of Finance, Government of India.

Government of India. Press Information Bureau. Various Press Releases.

Engelschalk, M., and Loeprick, J. (2015). MSME Taxation in Transition Economies: Country Experience on the Costs and Benefits of Introducing Special Tax Regimes (Policy Research Working Paper No. 7449). World Bank.

Mukherjee, S. (2025). Distributional Effects of GST in India: Evidence from the 2022-23 Household Consumption Expenditure Survey. Economic and Political Weekly.

के प्रभाव को दर्शाती है। पहली छमाही: 2025-26 में, राज्यों को सौंपे गए असाइनमेंट (यानी, केंद्र से राज्यों को कर हस्तांतरण) ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 14.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (बी)।

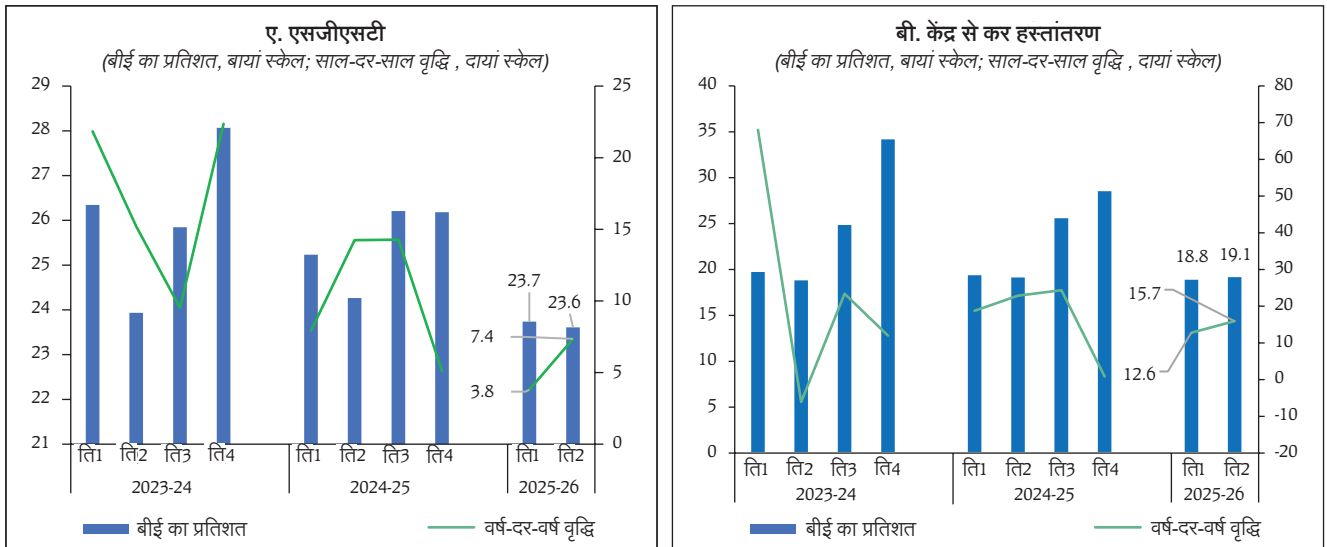
पहली छमाही: 2025-26 के दौरान, रिजर्व बैंक से उच्च अधिशेष हस्तांतरण के कारण, गैर-कर राजस्व स्रोतों से केंद्र की प्राप्तियों में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जिससे कर प्राप्तियों में कमी की भरपाई करने में मदद मिली। 2025-26 की पहली तिमाही और 2025-26 की दूसरी तिमाही के दौरान, गैर-कर राजस्व

में क्रमशः 33.2 प्रतिशत और 20.5 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। गैर-ऋण पूंजीगत²² प्राप्तियों ने पहली छमाही: 2025-26 (चार्ट 7) में मजबूत वृद्धि दर्ज की।

बी. व्यय

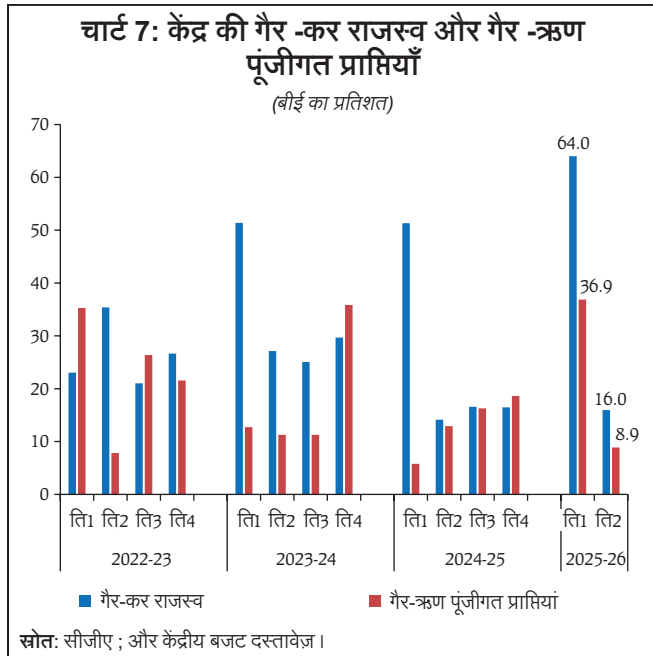
2025-26 में, केंद्र सरकार के कुल व्यय में 2024-25 (पीए) की तुलना में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जिसमें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय वृद्धि क्रमशः 9.5 प्रतिशत और 6.6 प्रतिशत है। पहली छमाही: 2025-26 में, खाद्य सब्सिडी में

चार्ट 6: केंद्र से एसजीएसटी और टैक्स ट्रांसफर का तिमाही निष्पादन



स्रोत: सीजीए।

22 विनिवेश प्राप्तियों सहित।



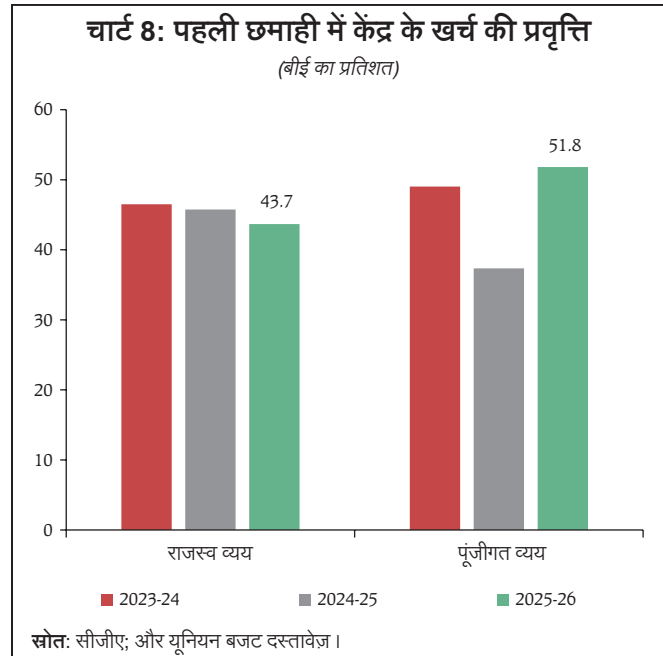
गिरावट के कारण बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम रहा। बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय पिछले वर्ष²³ की तुलना में काफी अधिक था, जिसके नेतृत्व में ऋण और अग्रिमों के साथ-साथ पूंजीगत परिव्यय²⁴ (चार्ट 8) में वृद्धि हुई।

शीर्ष 5 मंत्रालयों का पूंजीगत व्यय, जो 2025-26 के लिए केंद्र के कुल बजटीय पूंजीगत व्यय का लगभग 90 प्रतिशत है, पहली छमाही: 2025-26 के दौरान उनके बजट अनुमान का 49.3 प्रतिशत रहा, जो पहली छमाही: 2024-25 के दौरान बजट अनुमान के 37.1 प्रतिशत से अधिक है (चार्ट 9). सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और रेल मंत्रालय, जो 2025-26 के लिए केंद्र के कुल बजटीय पूंजीगत व्यय का 46.8 प्रतिशत हैं, ने पहली छमाही: 2025-26 में क्रमशः 21.7 प्रतिशत और 5.6 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की है।

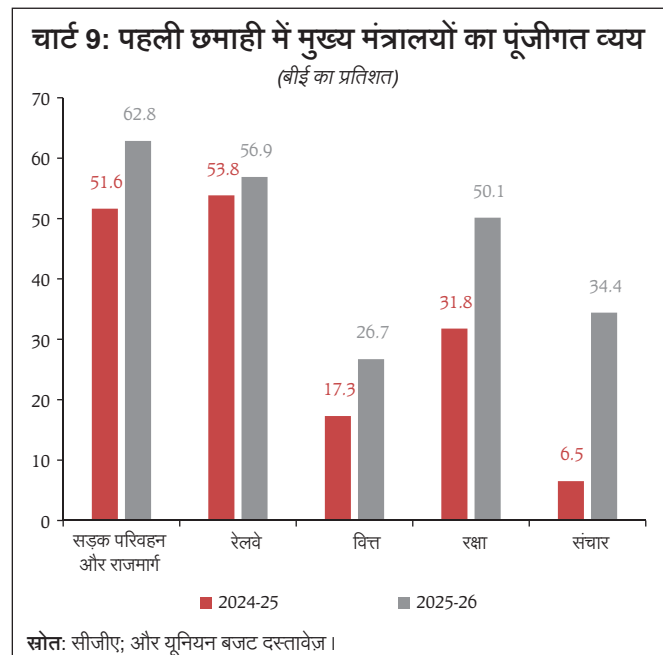
केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 2025-26 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग के पहले बैच का भी प्रस्ताव किया था, जिसमें 41,455 करोड़ रुपये का शुद्ध नकद

²³ पहली छमाही :2024-25 के दौरान बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में कम पूंजीगत व्यय मुख्य रूप से आम चुनावों और भारी मानसून की बारिश (ति. 2: 2024-25 में) के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता (ति. 1:2024-25 में) लागू करने के कारण था।

²⁴ पूंजीगत परिव्यय पूंजीगत व्यय कम ऋण और अग्रिम है।



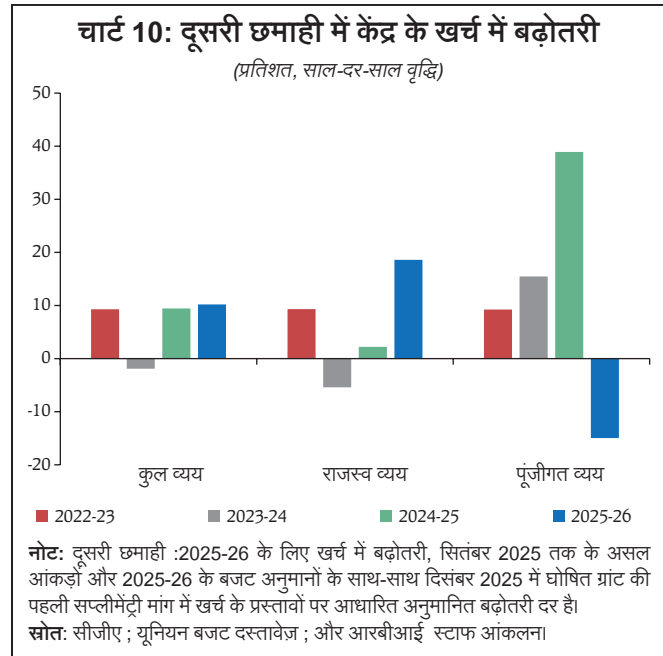
व्यय शामिल है। आगे बढ़ते हुए, दूसरी छमाही: 2024-25 की तुलना में, दूसरी छमाही: 2025-26 में कुल व्यय में वृद्धि मध्यम होने की संभावना है, क्योंकि केंद्र का लक्ष्य 2025-26 के लिए अपने बजटीय घाटे के लक्ष्य का पालन करना है। 2025-26 की दूसरी छमाही के दौरान, 2025-26 के बजटीय राजस्व व्यय लक्ष्य को पूरा करने के लिए राजस्व व्यय में वृद्धि 2025-26 की पहली छमाही में दर्ज की गई वृद्धि से अधिक होने की उम्मीद



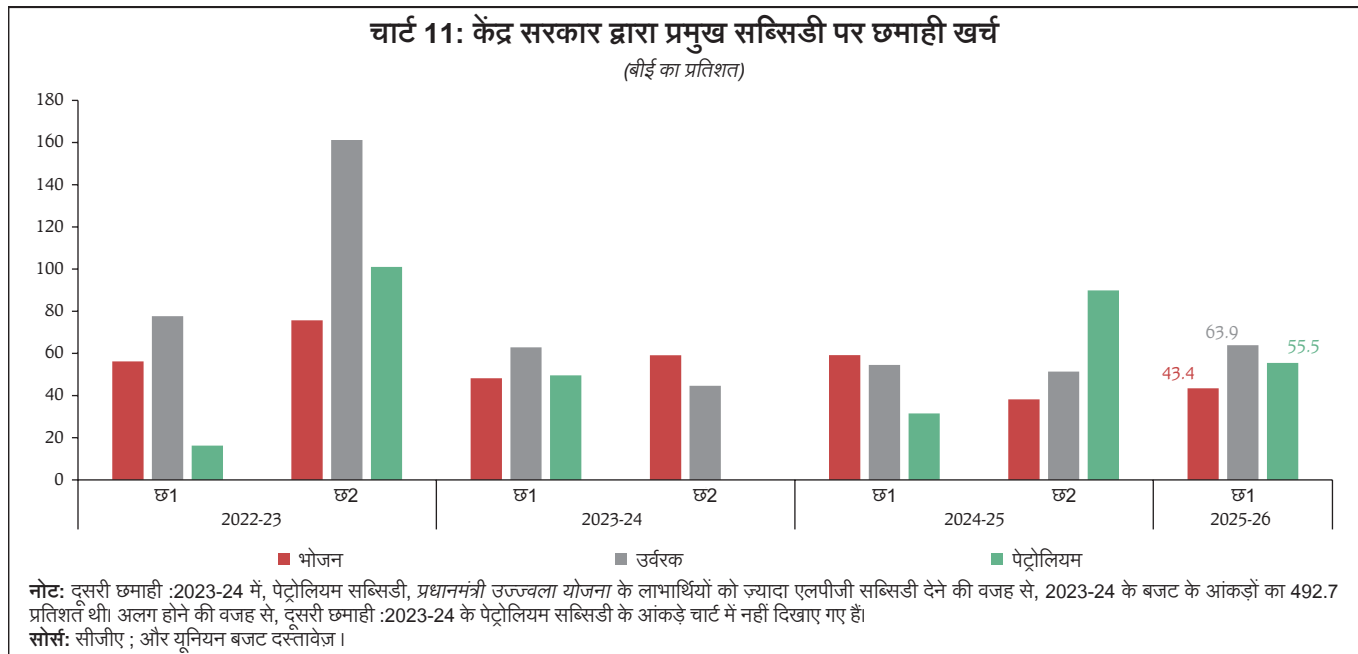
है। चूंकि 2024-25 के लिए बजटीय पूंजीगत व्यय का प्रमुख हिस्सा दूसरी छमाही: 2024-25 के दौरान किया गया था, इसलिए दूसरी छमाही: 2025-26 के दौरान पूंजीगत व्यय वृद्धि आधार प्रभाव को दर्शाते हुए वर्ष-दर-वर्ष आधार पर धीमी होने की संभावना है (चार्ट 10)।

खाद्य, ईंधन और उर्वरकों सहित प्रमुख सब्सिडी पर केंद्र सरकार का खर्च पहली छमाही: 2025-26 में बजट अनुमान का 52.8 प्रतिशत था, जबकि पहली छमाही: 2024-25 में बजट अनुमान का 56.3 प्रतिशत था। प्रमुख सब्सिडियों में यह गिरावट मुख्य रूप से खाद्य सब्सिडी में संकुचन के कारण है। उर्वरक सब्सिडी अन्य बातों के साथ-साथ यूरिया की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों और पोषक तत्व आधारित सब्सिडी²⁵ के कारण 2025-26 की पहली छमाही में बजटीय राशि का 63.9 प्रतिशत थी। पेट्रोलियम सब्सिडी, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना²⁶ के तहत सब्सिडी खर्च शामिल है, पहली छमाही: 2025-26 (चार्ट 11) के दौरान इसकी बजटीय राशि का 55.5 प्रतिशत था।

पहली छमाही: 2025-26 में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ राज्यों का राजस्व व्यय स्वस्थ रहा (चार्ट 12ए)। पिछले वर्ष के



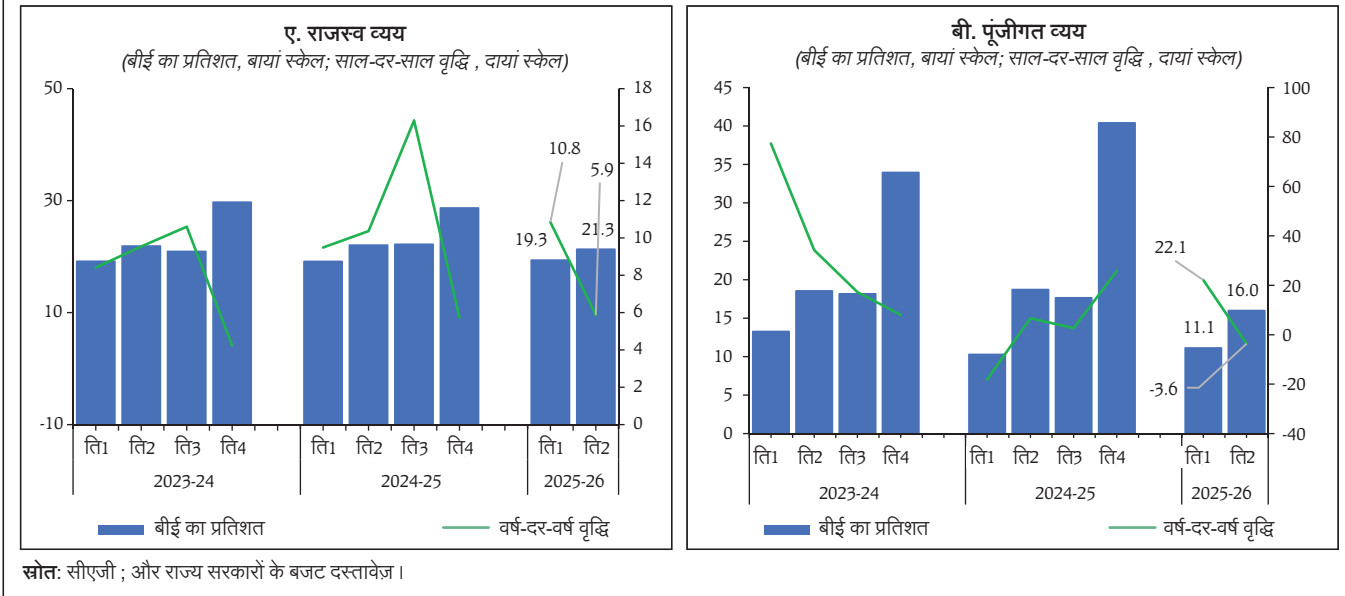
खर्च व्यवहार को ध्यान में रखते हुए, राज्यों ने 2025-26 की पहली छमाही में अपने बजटीय राजस्व व्यय का 40.6 प्रतिशत समाप्त कर दिया है। इस बीच, 2025-26 की पहली छमाही के दौरान पूंजीगत व्यय में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें कम



²⁵ मासिक बुलेटिन, उर्वरक विभाग, सितंबर 2025।

²⁶ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की घोषणा 1 मई, 2016 को पात्र परिवारों को सब्सिडी वाले तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) कनेक्शन प्रदान करने के लिए की गई थी ताकि उन्हें पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों से एलपीजी में बदलने में मदद मिल सके जो एक स्वच्छ ईंधन है।

चार्ट 12: राज्य सरकारों का तिमाही खर्च

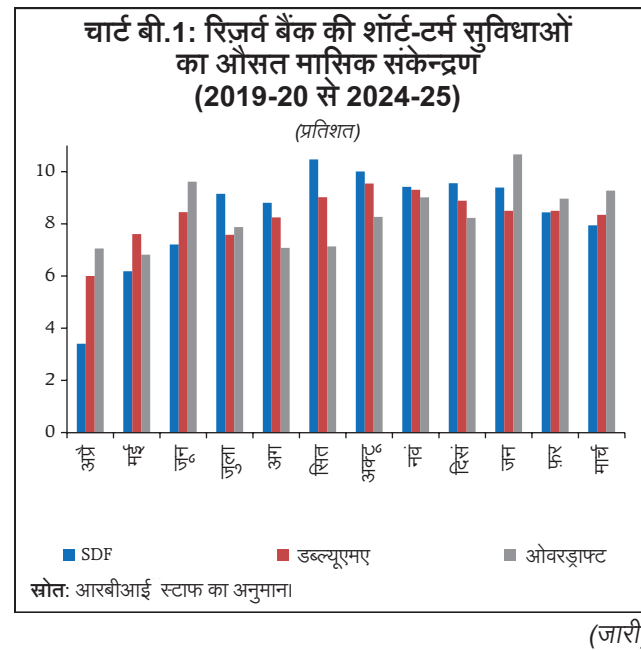


आधार के कारण पहली तिमाही में मजबूत वृद्धि देखी गई, जबकि दूसरी तिमाही (चार्ट 12बी) में संकुचन दर्ज किया गया। पूंजी निवेश के लिए केंद्र की ब्याज मुक्त ऋण योजना और वर्ष के अंत

में खर्च करने की सुविधा (बॉक्स बी) के माध्यम से पूंजीगत व्यय में तेजी आने की संभावना है।

बॉक्स बी : उप-राष्ट्रीय सरकारों में राजकोषीय समुच्चय का मौसमी संकेन्द्रण

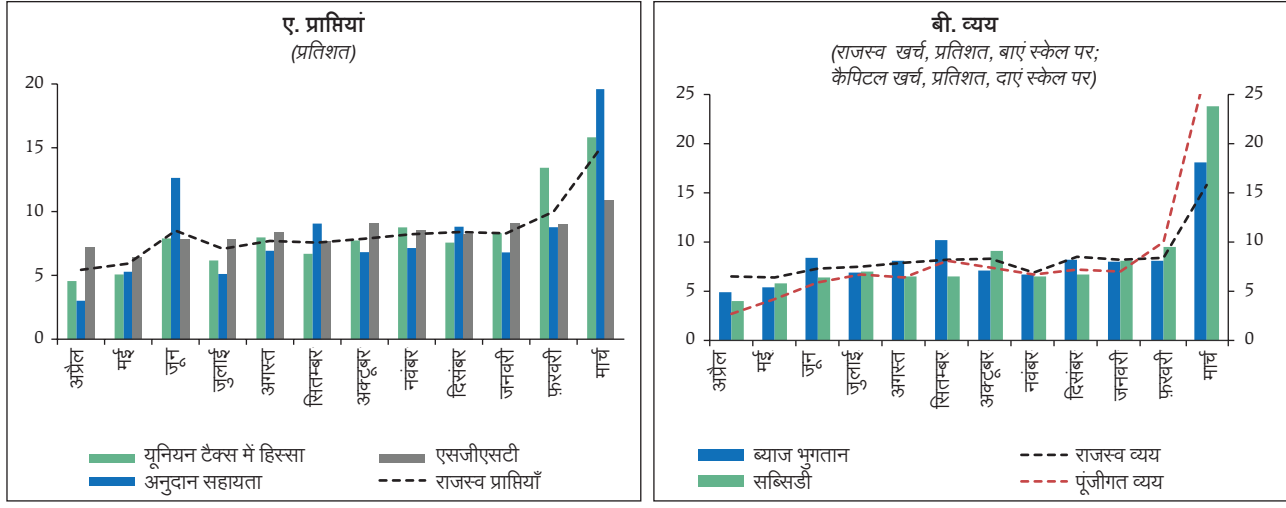
राजकोषीय समुच्चय का मौसमी संकेन्द्रण भारतीय राज्यों में नकदी प्रवाह प्रबंधन का एक केंद्रीय पहलू है, जो अक्सर उनकी अल्पकालिक उधार आवश्यकताओं को आकार देता है। जब राजस्व प्राप्तियों और व्यय प्रतिबद्धताओं का समय अलग-अलग हो जाता है, तो राज्यों को अस्थायी अंतराल का सामना करना पड़ता है जिसे भुगतान निरंतरता बनाए रखने के लिए पाटा जाना चाहिए। तदनुसार, राज्य भारतीय रिजर्व बैंक की नकदी सुविधाओं, नामतः विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ), अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) और ओवरड्राफ्ट (ओडी) की ओर मुड़ने से पहले अपने मध्यवर्ती ट्रेजरी बैलेंस पर भरोसा करते हैं। 2019-20 से 2024-25 के बीच, सितंबर तक एसडीएफ के उपयोग में लगातार वृद्धि हुई है। डब्ल्यूएमए का उपयोग त्योहारी तिमाही से पहले अक्टूबर में चरम पर होता है, जबकि ओवरड्राफ्ट का उपयोग जनवरी-मार्च में गति पकड़ता है, जो साल के अंत के व्यय चक्र के शुरुआती चरणों के साथ संरेखित होता है, जब व्यय आमतौर पर अपने साल के अंत के शिखर (चार्ट बी.1) को रिकॉर्ड करता है।



(जारी)

²⁷ एसडीएफ राज्यों को समेकित सिंकिंग फंड (सीएसएफ), गारंटी मोचन निधि (जीआरएफ) और सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक)/नीलामी ट्रेजरी बिलों (एटीबी) में निवेश के एवज में उनके निवेश की मात्रा से जुड़ी निधियों का उपयोग करने की अनुमति देता है। डब्ल्यूएमए नियमित नकदी-प्रवाह अंतराल को सुचारु करने के लिए अस्थायी अग्रिम प्रदान करता है, जबकि ओडी, जो रेपो दर से ऊपर दंडात्मक दर रखता है, केवल तभी लागू किया जाता है जब डब्ल्यूएमए सीमा पार हो जाती है और तेज नकदी तनाव का संकेत देती है।

चार्ट बी .2. प्रामियों और व्यय के घटकों में औसत मासिक सांद्रता (2019-20 से 2024-25)



स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमाना

लिए राज्यों की राजस्व प्रामियों के साथ-साथ इसके प्रमुख घटकों जैसे कर हस्तांतरण, राज्यों के माल और सेवा कर (एसजीएसटी) और केंद्र से अनुदान पर विचार किया जाता है (चार्ट बी.2ए)। समग्र पैटर्न कुल प्रामियों में एक स्पष्ट वर्ष के अंत की एकाग्रता को प्रकट करता है, जो प्रशासनिक और चक्रीय दोनों कारकों के प्रभाव को दर्शाता है। केंद्र से कर हस्तांतरण मार्च में अपने चरम पर पहुंच गया है, जो केंद्रीय कर हस्तांतरण और अग्रिम कर प्रवाह के साल के अंत में निपटान के साथ मेल खाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केंद्र का कॉर्पोरेट कर और आयकर संग्रह स्वयं अग्रिम भुगतान अनुसूची और खातों को अंतिम रूप देने के इर्द-गिर्द क्लस्टर होता है (श्रीवास्तव और त्रेहन, 2018; श्रीवास्तव एट अल., 2025)। अनुदान में सहायता जून में एक अलग स्थानीय शिखर²⁸ रिकॉर्ड करता है, इसके बाद सितंबर और दिसंबर में हल्की चोटियों का होता है, और मार्च में एक स्पष्ट वार्षिक वृद्धि होती है, जो योजना से संबंधित हस्तांतरणों के विशिष्ट गुच्छा को दर्शाती है। इसके विपरीत, एसजीएसटी संग्रह, खपत और आर्थिक गतिविधि से निकटता से जुड़ा हुआ है, जो हल्के उत्सव-मौसम के चरम के साथ अपेक्षाकृत स्थिर प्रवाह दिखाता है।

राज्यों का माह-वार व्यय पैटर्न राजस्व व्यय के साथ एक अलग बैक-लोडेड संकेन्द्रण (चार्ट बी.2बी) प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा प्रकृति में प्रतिबद्ध है। अप्रैल और मई में, कुल खर्च

गतिविधि कम रहती है, जैसा कि विभिन्न राज्यों में देखा गया है। जून के बाद से खर्च में तेजी आने लगती है। राज्य सरकार के खर्च में फरवरी और मार्च में साल के अंत में वृद्धि देखी जाती है, जब विभाग अनुदान के तहत योजनाओं से धन के प्रवाह के बाद परियोजना निष्पादन में तेजी लाते हैं और विभाग भी धन की चूक से बचने के लिए लंबित बिलों का भुगतान करते हैं। इन अंतिम महीनों में विशेष रूप से पूंजीगत व्यय में खर्च में तेजी से वृद्धि तरलता के दबाव को तेज करती है, जो अक्सर राज्यों को अल्पकालिक उधार पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करती है। एसडीएफ और डब्ल्यूएमए जैसी नियमित सस्ती उधार सुविधाओं के समाप्त होने के साथ, कई राज्य अस्थायी नकदी अंतराल को पाटने के लिए ओवरड्राफ्ट तंत्र का सहारा लेते हैं। यह अस्थायी उधार सुविधाओं पर निर्भरता को कम करने के लिए सुचारु अंतर-वर्ष व्यय अंशांकन की आवश्यकता को पुष्ट करता है।

संदर्भ

Srivastava, D. K., and Trehan, R. (2018). Managing Central Government Finances: Asymmetric Seasonality in Receipts and Expenditures. *Global Business Review*, 19(5), 1322-1344.

Srivastava, D. K., Bharadwaj, M., Kapur, T., and Trehan, R. (2025). Seasonal Concentration of Fiscal Aggregates: Case Study of India. *Modern Economy*, 16(9).

²⁸ एक स्थानीय शिखर एक ऐसा महीना होता है जहां सांद्रता उसके ठीक पहले और बाद के महीनों की तुलना में अधिक होती है।

III. राजकोषीय घाटा और इसका वित्तपोषण

केंद्र सरकार

ए . राजकोषीय घाटा

केंद्र सरकार ने 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.4 प्रतिशत की तुलना में 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.4 प्रतिशत के जीएफडी का बजट रखा है, जो 2025-25 (पीए) में 4.8 प्रतिशत की तुलना में 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से कम के मध्यम अवधि के जीएफडी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए है। जबकि ति. 1:2025-26 में जीएफडी-जीडीपी अनुपात पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में अधिक था, ति. 2:2025-26 में ट्रेड उलट गया। पहली छमाही: 2025-26 के दौरान, केंद्र सरकार का जीएफडी बजट अनुमान का 36.5 प्रतिशत रहा, जो पहली छमाही: 2024-25 के दौरान दर्ज किए गए 29.4 प्रतिशत से अधिक है, जो केंद्र के पूंजीगत व्यय में उच्च वृद्धि को दर्शाता है (चार्ट 13ए और बी)।

बी. जीएफडी का वित्तपोषण

पहली छमाही: 2025-26 (26 सितंबर, 2025 तक) में, केंद्र सरकार ने 2025-26 के लिए बजटीय शुद्ध बाजार उधार का 48.2 प्रतिशत पूरा किया (पिछले वर्ष की इसी अवधि में 43.9 प्रतिशत के मुकाबले), जिसने इसके जीएफडी के एक बड़े हिस्से को वित्तपोषित किया।

राज्य सरकार

ए . राजकोषीय घाटा

राज्यों ने 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 3.3

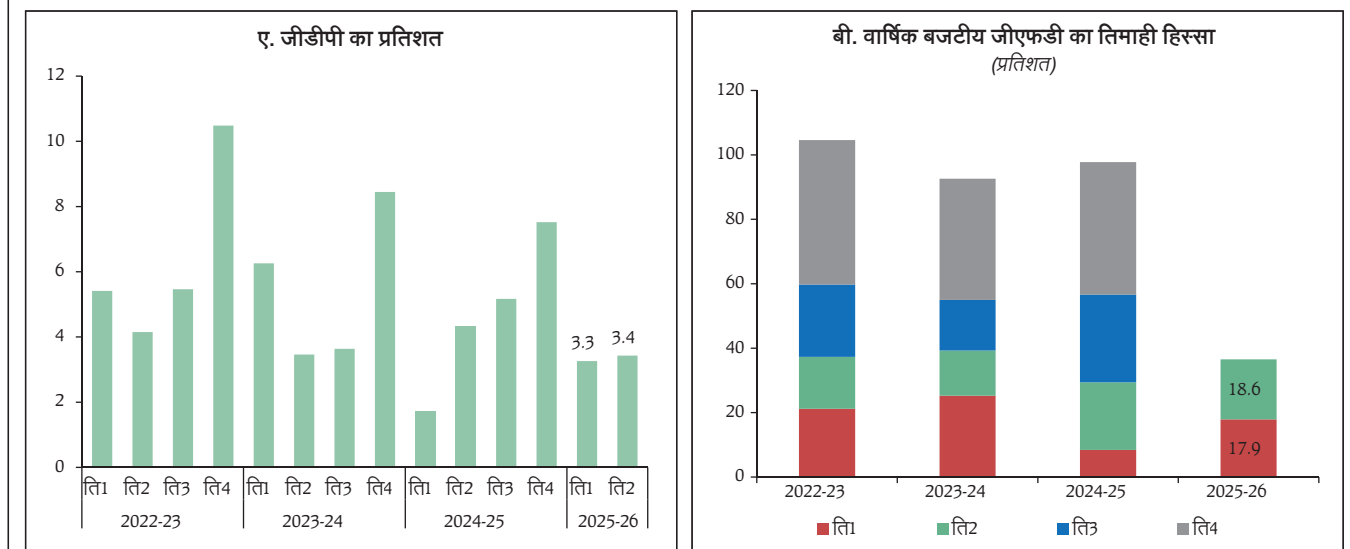
प्रतिशत का समेकित जीएफडी का बजट रखा, जो 2024-25 (आरई) में 3.5 प्रतिशत से कम है। राज्यों ने 2024-25 की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही की तुलना में क्रमशः 2025-26 की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में अपने बजटीय जीएफडी का मामूली रूप से अधिक अनुपात हासिल किया है। इसी तरह, 2025-26 की दूसरी छमाही के लिए राज्यों के लिए उपलब्ध राजकोषीय स्थान उनके बजटीय जीएफडी का 62.4 प्रतिशत तक थोड़ा कम हो गया है, जबकि एच2:2024-25 (चार्ट 14ए और बी) के दौरान उपलब्ध 62.9 प्रतिशत है।

बी . जीएफडी का वित्त पोषण

पहली छमाही: 2025-26 के दौरान राज्यों की शुद्ध बाजार उधारी में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 22.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान, राज्यों ने अपने बजटीय शुद्ध बाजार उधार का 35.9 प्रतिशत उपयोग किया, जो 2024-25 की इसी अवधि में 32.1 प्रतिशत था। सत्रह राज्यों ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अपने बजटीय शुद्ध उधार के उच्च अनुपात का उपयोग किया (चार्ट 15 ए और बी)। सकल बाजार उधार में पिछले वर्ष की तुलना में 21.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो बजटीय राशि का 37.5 प्रतिशत है।

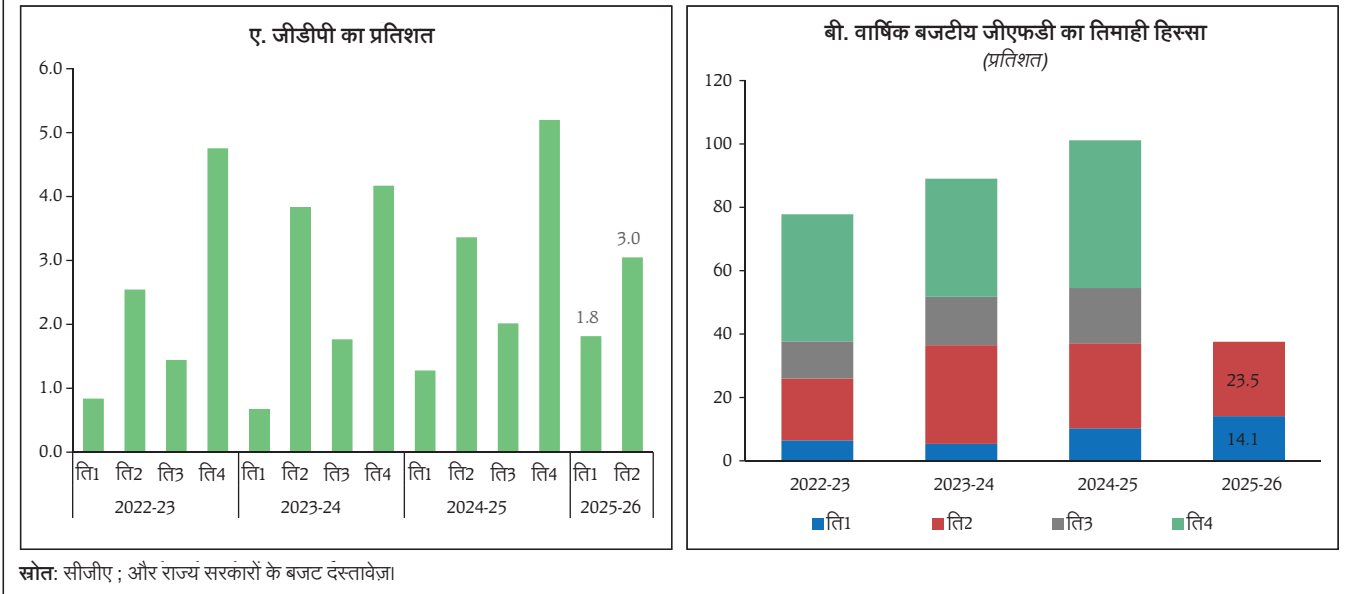
रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सुविधाओं के माध्यम से राज्यों द्वारा प्राप्त वित्तीय समायोजन में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में पहली छमाही: 2025-26 में 52.7

चार्ट 13: केंद्र का सकल राजकोषीय घाटा



स्रोत: सीजीए ; और यूनिनियन बजट दस्तावेज़।

चार्ट 14: राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा



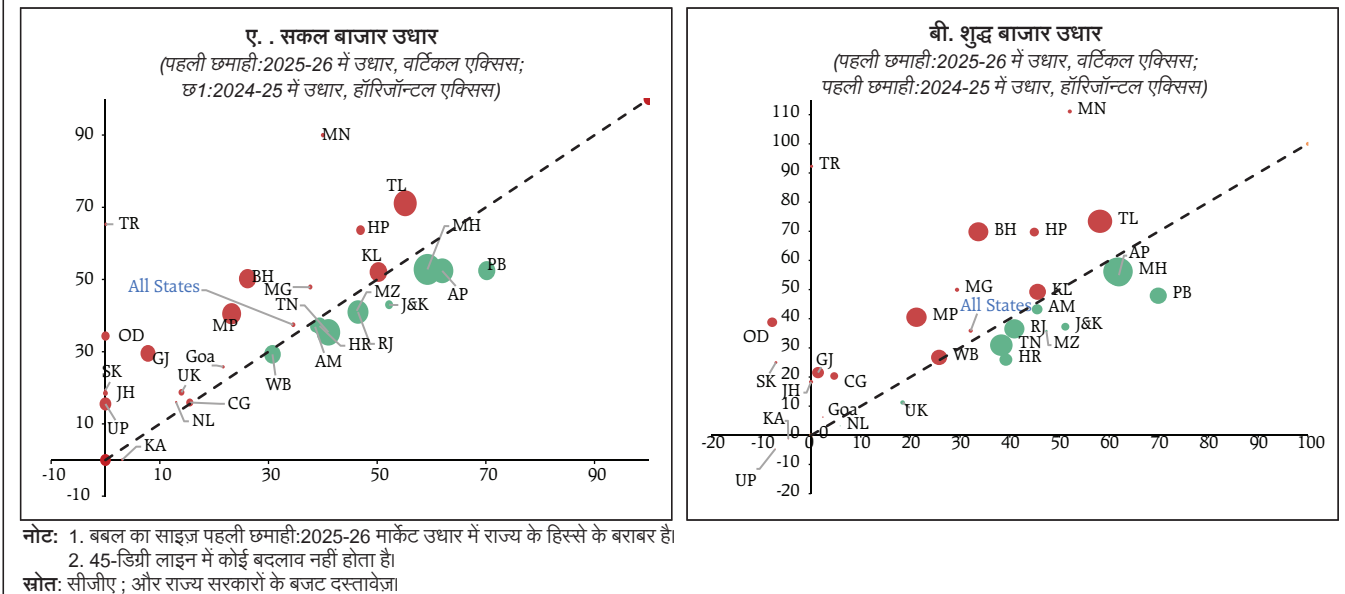
प्रतिशत की वृद्धि हुई। तरीके और साधन अग्रिम (डबल्यूएमए) सीमा को 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी रूप से संशोधित किया गया था। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल डबल्यूएमए सीमा अब 60,118 करोड़ रुपये है, जो पहले की 47,010 करोड़ रुपये की सीमा से 27.9 प्रतिशत अधिक है। राज्यों ने ति. 1:2025-26 में अनुमेय डबल्यूएमए सीमा का 8.1 प्रतिशत और ति. 2:2025-26 में 10.6 प्रतिशत का उपयोग किया। सभी तीन सुविधाओं

के तहत राज्यों द्वारा औसत उपयोग जैसे विशेष ड्राइंग सुविधा, तरीके और साधन अग्रिम और ओवरड्राफ्ट पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में पहली छमाही: 2025-26 के दौरान बढ़ गया (चार्ट 16 ए और बी)।

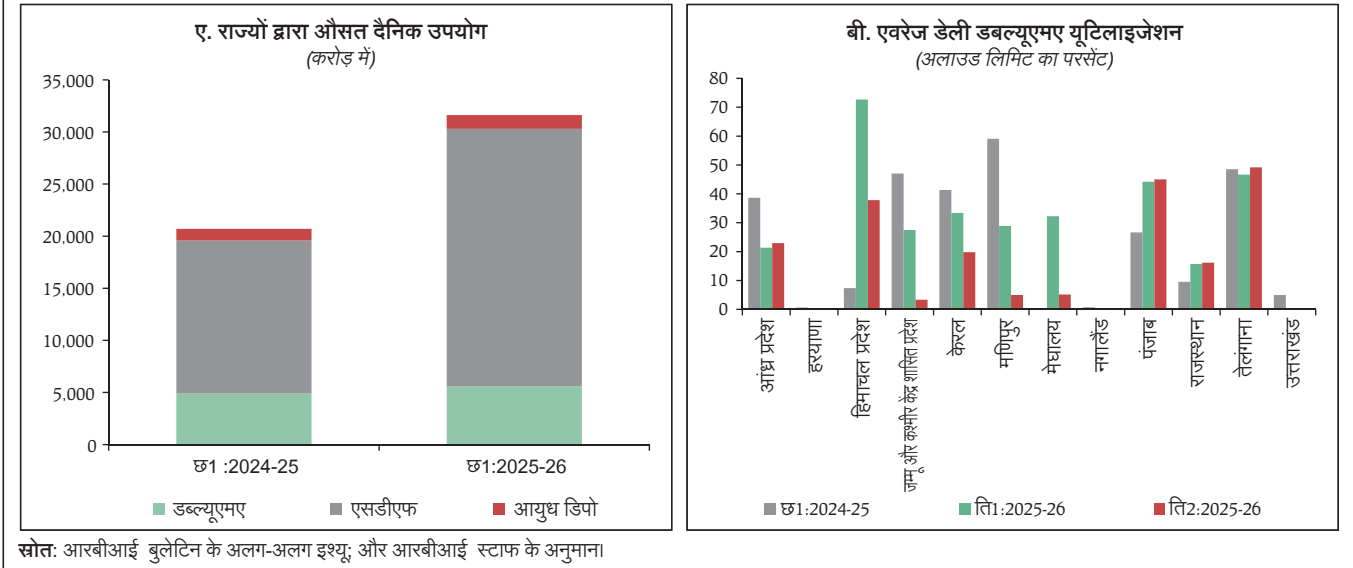
व्यय की गुणवत्ता – केंद्र और राज्य

केंद्र का राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय (आरईसीओ) अनुपात एक साल पहले के 4.7 से घटकर 2025-26 की पहली

चार्ट 15: राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार बाज़ार उधारी



चार्ट 16: राज्यों को रिज़र्व बैंक से अलग-अलग सुविधाओं के तहत मिली वित्तीय सहायता

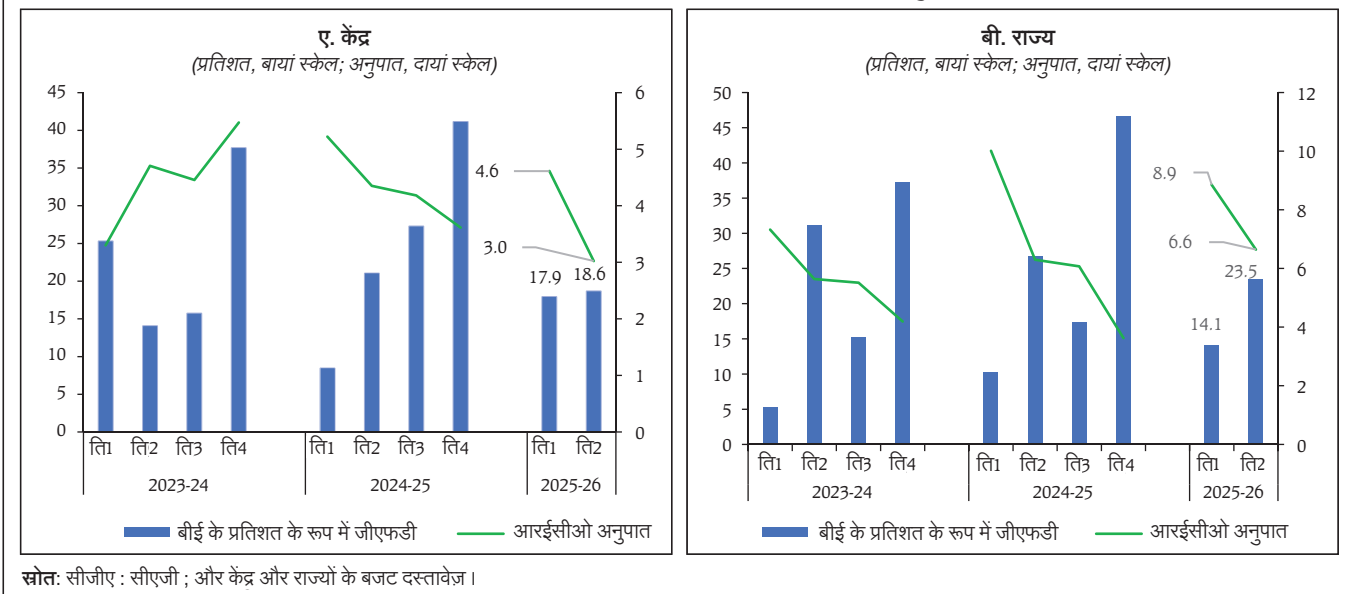


छमाही में 3.7 हो गया, जो एक दशक से अधिक समय में सबसे कम है। इसी तरह, राज्यों के मामले में, व्यय की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, जैसा कि पिछले वर्ष की तुलना में पहली छमाही: 2025-26 में आरईसीओ अनुपात में गिरावट में परिलक्षित होता है (चार्ट 17b)।

IV. सामान्य सरकारी वित्त

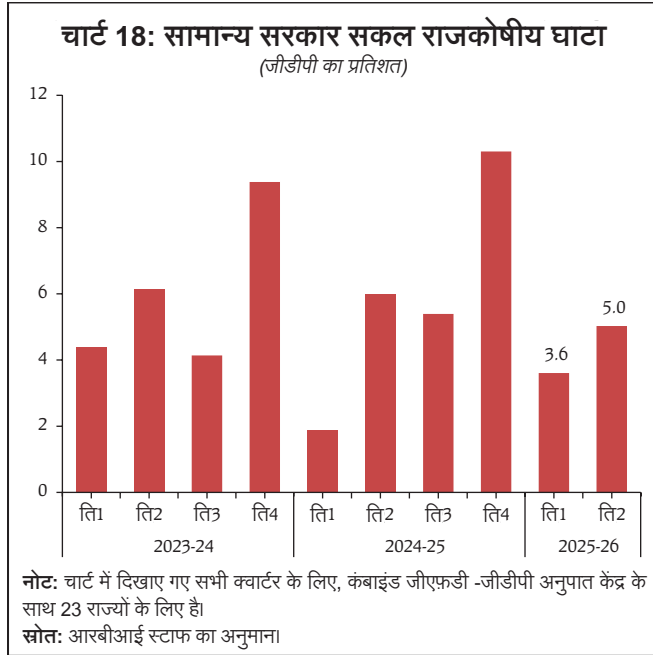
सामान्य सरकार पर समय पर राजकोषीय डेटा प्रदान करने के प्रयास को जारी रखते हुए, सामान्य सरकार की तिमाही राजकोषीय स्थिति को ति. 2:2025-26 तक संकलित किया गया है। 2025-26 की पहली तिमाही में, मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय में उच्च वृद्धि के कारण केंद्र और राज्यों के संयुक्त व्यय

चार्ट 17: सकल राजकोषीय घाटा और व्यय की गुणवत्ता



²⁹ कम आरईसीओ अनुपात का अर्थ है सरकार के लिए व्यय की गुणवत्ता में सुधार।

में वृद्धि के परिणामस्वरूप जीएफडी में वृद्धि हुई। हालांकि, ति. 2:2025-26 में, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जीएफडी को वर्ष-दर-वर्ष आधार पर कम किया गया, जो मुख्य रूप से राजस्व व्यय की रोकथाम के कारण था (चार्ट 18)।



V. निष्कर्ष

पहली छमाही: 2025-26 के दौरान, कर प्राप्तियों में कमी की आंशिक रूप से केंद्र की मजबूत गैर-कर राजस्व के साथ-साथ गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों द्वारा भरपाई की गई थी। कुल मिलाकर, केंद्र ने पहली छमाही: 2025-26 में अपने बजटीय राजस्व का लगभग आधा संग्रह किया है, जबकि 2025-26 के लिए बजट अनुमानों के आधे से भी कम अपने व्यय को नियंत्रित किया है। यह केंद्र के लिए 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 4.4 प्रतिशत के जीएफडी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अच्छा संकेत है। राज्यों के मामले में, पहली छमाही: 2025-26 के दौरान बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में उनका जीएफडी पहली छमाही: 2024-25 की तुलना में केवल मामूली रूप से अधिक था, जो मुख्य रूप से उनकी राजस्व प्राप्तियों में कम वृद्धि के कारण था। व्यय के मोर्चे पर, राज्यों ने पूंजीगत व्यय को बनाए रखते हुए अपने राजस्व व्यय को बनाए रखा। आगे बढ़ते हुए, राज्यों को समग्र स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए राजकोषीय समेकन के साथ-साथ अपने पूंजीगत व्यय की गति को बनाए रखने की आवश्यकता है।

परिशिष्ट सारणी

सारणी I: अप्रैल-सितंबर के दौरान केंद्र सरकार की बजटीय स्थिति

वस्तु	(₹ हजार करोड़)				(प्रतिशत)			
	वास्तविक आंकड़े: पहली रिपोर्ट		बजट अनुमान (बीई)		बीई का प्रतिशत		वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	
	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. राजस्व प्राप्तियां	1,622.4	1,695.4	3,129.2	3,420.4	51.8	49.6	16.1	4.5
(i) शुद्ध कर राजस्व	1,265.2	1,229.4	2,583.5	2,837.4	49.0	43.3	9.0	-2.8
(ii) गैर-कर राजस्व	357.2	466.1	545.7	583.0	65.5	79.9	50.9	30.5
(iii) ब्याज प्राप्तियां	20.4	18.0	38.2	47.7	53.3	37.7	17.6	-11.5
2. गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	14.6	34.8	78.0	76.0	18.7	45.8	-27.6	138.1
(i) ऋणों की वसूली	11.4	11.4	28.0	29.0	40.8	39.1	-13.5	-0.7
(ii) विविध पूंजी प्राप्तियां	3.2	23.4	50.0	47.0	6.3	49.8	-54.4	639.4
3. कुल प्राप्तियां (1+2)	1,637.0	1,730.2	3,207.2	3,496.4	51.0	49.5	15.5	5.7
4. राजस्व व्यय	1,696.5	1,722.6	3,709.4	3,944.3	45.7	43.7	4.2	1.5
(i) ब्याज भुगतान	515.0	578.2	1,162.9	1,276.3	44.3	45.3	6.3	12.3
5. पूंजीगत व्यय	415.0	580.7	1,111.1	1,121.1	37.3	51.8	-15.4	40.0
(i) ऋण और अग्रिम	55.4	118.9	192.4	225.8	28.8	52.6	-25.9	114.6
(ii) पूंजीगत परिव्यय	359.6	461.9	918.7	895.2	39.1	51.6	-13.5	28.5
6. कुल व्यय (4 + 5)	2,111.5	2,303.3	4,820.5	5,065.3	43.8	45.5	-0.4	9.1
7. राजस्व घाटा (4 - 1)	74.2	27.1	580.2	523.8	12.8	5.2	-68.0	-63.4
8. राजकोषीय घाटा (6 - 3)	474.5	573.1	1,613.3	1,568.9	29.4	36.5	-32.4	20.8
9. सकल प्राथमिक घाटा {8 - 4(i)}	-40.5	-5.1	450.4	292.6	-9.0	-1.7	-118.6	87.5

नोट: नेगेटिव प्राइमरी डेफिसिट प्राइमरी सरप्लस दिखाता है।

स्रोत: कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स; और यूनियन बजट दस्तावेज़।

सारणी II: केंद्र सरकार के वित्त की तिमाही स्थिति

वस्तु	(₹ हजार करोड़)				(प्रतिशत)					
	वास्तविक				बजट अनुमानों का प्रतिशत				वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	
	प्रश्न 1		प्रश्न 2		प्रश्न 1		प्रश्न 2		2025-26	
	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	ति1	ति2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. राजस्व प्राप्तियां	829.7	913.4	792.7	782.1	26.5	26.7	25.3	22.9	10.1	-1.3
(i) शुद्ध कर राजस्व	549.6	540.3	715.5	689.1	21.3	19.0	27.7	24.3	-1.7	-3.7
(ii) गैर-कर राजस्व	280.0	373.1	77.2	93.0	51.3	64.0	14.1	16.0	33.2	20.5
(iii) ब्याज प्राप्तियां	11.7	9.7	8.6	8.3	30.6	20.3	22.6	17.4	-17.2	-3.8
2. गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	4.5	28.0	10.1	6.8	5.8	36.9	12.9	8.9	519.9	-33.0
ऋणों की वसूली	4.5	5.4	6.9	6.0	16.1	18.6	24.7	20.5	19.5	-13.9
(ii) विविध पूंजी प्राप्तियां	0.0	22.6	3.2	0.8	0.0	48.1	6.3	1.7	5,65,475.0	-74.9
3. कुल प्राप्तियां (1+2)	834.2	941.4	802.8	788.8	26.0	26.9	25.0	22.6	12.9	-1.7
4. राजस्व व्यय	788.9	947.0	907.7	775.6	21.3	24.0	24.5	19.7	20.0	-14.6
(i) ब्याज भुगतान	264.1	386.0	251.0	192.1	22.7	30.2	21.6	15.1	46.2	-23.4
5. पूंजीगत व्यय	181.1	275.1	233.9	305.6	16.3	24.5	21.1	27.3	52.0	30.7
(i) ऋण और अग्रिम	30.0	69.8	25.4	49.0	15.6	30.9	13.2	21.7	132.7	93.2
(ii) पूंजीगत परिव्यय	151.0	205.3	208.5	256.6	16.4	22.9	22.7	28.7	35.9	23.0
6. कुल व्यय (4 + 5)	969.9	1,222.1	1,141.6	1081.2	20.1	24.1	23.7	21.3	26.0	-5.3
7. राजस्व घाटा (4 - 1)	-40.8	33.6	115.0	-6.5	-7.0	6.4	19.8	-1.2	182.4	-105.6
8. राजकोषीय घाटा (6 - 3)	135.7	280.7	338.8	292.4	8.4	17.9	21.0	18.6	106.9	-13.7
9. सकल प्राथमिक घाटा {8 - 4(i)}	-128.3	-105.3	87.8	100.2	-28.5	-36.0	19.5	34.3	17.9	14.1

नोट: नेगेटिव राजस्व डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट क्रमशः राजस्व सरप्लस और प्राइमरी सरप्लस दिखाते हैं।

स्रोत: कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स; और यूनियन बजट दस्तावेज।

सारणी III: अप्रैल-सितंबर 2025 के दौरान राज्य सरकारों की बजटीय स्थिति

वस्तु	(₹ हजार करोड़)				(प्रतिशत)			
	वास्तविक आंकड़े: पहली रिपोर्ट		बजट अनुमान		बीई का प्रतिशत		वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	
	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. राजस्व प्राप्तियां	1,682.8	1,788.5	4,231.3	4,636.0	39.8	38.6	7.2	6.3
1.1 कर राजस्व	1,395.3	1,523.6	3,244.7	3,605.8	43.0	42.3	12.1	9.2
1.2. गैर-कर राजस्व	123.3	133.7	372.1	411.1	33.1	32.5	-7.5	8.4
1.3. अनुदान सहायता और अंशदान	164.2	131.3	614.6	619.1	26.7	21.2	-14.2	-20.1
2. गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	2.8	6.0	43.7	48.9	6.3	12.2	-30.9	116.6
2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	2.7	5.9	20.6	24.0	13.1	24.7	-26.0	119.9
2.2. अन्य विविध पूंजी प्राप्तियां	0.1	0.0	23.1	24.9	0.3	0.2	-82.1	-27.9
3. कुल प्राप्तियां	1,685.6	1,794.5	4,275.1	4,684.9	39.4	38.3	7.1	6.5
4. राजस्व व्यय	1,780.1	1,925.8	4,326.4	4,740.2	41.1	40.6	10.0	8.2
4.1 ब्याज भुगतान	230.6	257.9	527.8	586.1	43.7	44.0	11.8	11.8
5. पूंजीगत व्यय	269.9	284.7	931.3	1,051.4	29.0	27.1	-3.7	5.5
5.1 पूंजीगत परिव्यय	233.9	255.4	850.9	972.2	27.5	26.3	-8.7	9.2
6. कुल व्यय	2,050.1	2,210.5	5,257.7	5,791.6	39.0	38.2	7.9	7.8
7. राजस्व घाटा (4-1)	97.3	137.3	95.0	104.2	102.4	131.7	98.2	41.0
8. राजकोषीय घाटा (6-3)	364.5	416.0	982.6	1,106.7	37.1	37.6	12.1	14.1
9. सकल प्राथमिक घाटा (8 - 4.1)	133.9	158.1	454.8	520.6	29.4	30.4	12.4	18.1

नोट: डेटा 23 राज्यों से संबंधित है।

स्रोत: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षका।

सारणी IV: राज्य सरकार के वित्त की तिमाही स्थिति

वस्तु	(₹ हजार करोड़)				(प्रतिशत)					
	वास्तविक				बीई का प्रतिशत				वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि	
	प्रश्न 1		प्रश्न 2		प्रश्न 1		प्रश्न 2		2025-26	
	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	ति1	ति2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. राजस्व प्राप्तियां	820.4	874.3	862.4	914.2	19.4	18.9	20.4	19.7	6.6	6.0
1.1 कर राजस्व	701.2	752.5	694.0	771.0	21.6	20.9	21.4	21.4	7.3	11.1
1.2. गैर-कर राजस्व	62.2	64.9	61.1	68.8	16.7	15.8	16.4	16.7	4.4	12.5
1.3. अनुदान सहायता और अंशदान	57.0	56.8	107.2	74.5	9.3	9.2	17.4	12.0	-0.4	-30.5
2. गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	1.4	3.1	1.4	2.9	3.1	6.3	3.2	5.9	127.5	106.0
2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	1.3	3.1	1.4	2.9	6.4	12.7	6.6	11.9	130.4	109.8
2.2. अन्य विविध पूंजी प्राप्तियां	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	-6.8	-45.6
3. कुल प्राप्तियां	821.8	877.4	863.8	917.1	19.2	18.7	20.2	19.6	6.8	6.2
4. राजस्व व्यय	827.1	916.8	953.0	1,009.0	19.1	19.3	22.0	21.3	10.8	5.9
4.1 ब्याज भुगतान	101.0	106.3	129.7	151.5	19.1	18.1	24.6	25.9	5.3	16.9
5. पूंजीगत व्यय	95.7	116.8	174.3	167.9	10.3	11.1	18.7	16.0	22.1	-3.6
5.1 पूंजीगत परिव्यय	82.6	103.5	151.3	151.8	9.7	10.6	17.8	15.6	25.3	0.3
6. कुल व्यय	922.8	1,033.6	1,127.3	1,176.9	17.6	17.8	21.4	20.3	12.0	4.4
7. राजस्व घाटा	6.7	42.5	90.7	94.8	7.0	40.8	95.4	91.0	537.4	4.5
8. राजकोषीय घाटा (6-3)	101.0	156.2	263.5	259.8	10.3	14.1	26.8	23.5	54.7	-1.4
9. सकल प्राथमिक घाटा (8 - 4.1)	0.0	49.9	133.9	108.3	0.0	9.6	29.4	20.8	-	-19.1

नोट: डेटा 23 राज्यों से संबंधित है।

स्रोत: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक।